साप्ताहिक
शांति मिशन
नई दिल्ली

वर्ष-29 अंक- 09 27 फरवरी - 05 मार्च 2022 पृष्ठ 12

अन्दर पढ़िए

जासूसी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न पृष्ठ-6

आख़िर उत्तर प्रदेश प्रगति की राह कब पकड़ेगा? पृष्ठ-7

अमीरों और ग़रीबों के नाम पर अस्तित्व में आ चुके हैं

दो भारत

संसद में राहुल गांधी की ललकार

संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने यह कह कर सब को चौंका दिया कि भारत दो भागों में विभाजित हो चुका है, एक अमीरों का भारत है और दूसरा ग़रीबों का भारत। श्री राहुल गांधी ने जो कहा है वह आज हमारे देश का एक ऐसा सत्य है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के संबोधन पर तहरीक में हिस्सा लेते हुए यह कहकर पूरे देश और लोकसभा को चौंका दिया कि भारत दो हिस्सों में बंटा हुआ है एक अमीरों का भारत है और दूसरा ग़रीबों का भारत, हालांकि बहस का जवाब देते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने उस पर लीपा-पोती करने की कोशिश की है मगर यह एक कड़वी सच्चाई है कि भारत कभी भी सबके लिए बराबर का देश नहीं रहा। असमानता यहां स्थायी है। हमारे राजा-महाराजा प्रजा को लूटते रहे और खुद विलास की ज़िन्दगी व्यतीत करते रहे। अंग्रेज़ों ने तो बाक़ायदा एक विशेषाधिकार सम्पन्न वर्ग स्थापित कर दिया और उन्हें 'सर', 'रायबहादुर', 'रायज़ादा' जैसे ख़िताबों से नवाज़ा गया। आज़ादी के बाद आशा बढ़ी कि वह ग़ैर बराबरी अगर ख़त्म नहीं होती तो कम तो हो ही जाएगी। हमारे संविधान का 'प्रीएम्बल' अर्थात् प्रस्तावना जहां 'सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय' पर जोर देता है, वहां 'अवसर की समता' का संकल्प भी व्यक्त करता है। 1976 में आपातकाल के दौरान इसमें भारत को 'समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य' बनाने का भी वायदा जोड़ा गया। 'समाजवाद' जोड़ने का भी यही उद्देश्य था कि यहां सबको बराबरी का अवसर मिलेगा। पर अब जबकि हम एक और गणतंत्र दिवस से गुज़र के हटे हैं, कड़ी सच्चाई है कि समाजवाद को एक ओर फेंकते हुए हम पूरी तरह से पूंजीवादी देश बन रहे हैं और कम होने की जगह यहां असमानता बढ़ी ही नहीं जम गई है। वैसे तो समाजवाद अपने मक्का मास्को और बीजिंग में भी दफना दिया गया है, पर भारत में ऐसा करने से बहुत बड़ी संख्या बहुत बड़ी कीमत चुका रही है।

गैर सरकारी संगठन ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में जब आम भारतीयों को रोज़गार का संकट था और 84 प्रतिशत परिवारों की आय में भारी गिरावट आई थी और कइयों पर तो दो वक़्त की रोटी की परेशानी थी, देश में अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई। 2017 में देश के टॉप 1 प्रतिशत के पास देश की दौलत का 73 प्रतिशत था। तब से लेकर अब तक स्थिति और ख़राब हुई है। देश के सबसे अमीर 98 लोगों के पास 55.5 करोड़ उनके ग़रीब देशवासियों के बराबर दौलत है जो 49 लाख करोड़ रुपए बनती है। इन 98 लोगों की दौलत भारत सरकार के बजट का 41 प्रतिशत है।

पीईडब्लयू की रिसर्च के अनुसार पिछले वर्ष देश के मिडल क्लास की संख्या 3.2 करोड़ कम हुई है पर देश के सुपर रिच के लिए यह महामारी तो छींका टूटा से कम नहीं क्योंकि लॉकडाउन की अवधि में उनकी दौलत 35 प्रतिशत तक बढ़ी है।

विश्व असमानता रिपोर्ट के अनुसार यहां अमीरों और ग़रीबों के बीच फासला बढ़ा है और ऊपर के 10 प्रतिशत के पास राष्ट्रीय आय का 57 प्रतिशत है और निचले 50 प्रतिशत के पास इसका केवल 13 प्रतिशत है।

अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के अनुसार 2020 में और 7.5 करोड़ लोग मुकम्मल ग़रीबी में फंस गए हैं। करोड़ों आज 6 किलो अनाज और दाल की ज़िन्दगी पर गुज़ारे करने को मजबूर हैं।

दिलचस्प आंकड़ा जो रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी. सुब्बाराव ने साझा किया है, के अनुसार पिछले साल उग्र दूसरी लहर के दौरान जून में जब लाखों लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे मर्सीडिज की सुपर लग्जरी एसयूवी ने सबसे अधिक मासिक सेल दर्ज की थी। स्टॉक मार्किट भी लगातार उछलता रहा।

2020-21 में यूथ बेरोज़गार रेट 28.26 प्रतिशत था जो 2016-17 में 15.66 प्रतिशत था। 2019-20 की तुलना में 2020-21 में लगभग 22.6 प्रतिशत कम रोज़गार मिला है। अप्रैल 2020 में हर घंटे में 17000 लोग अपना रोज़गार गंवा रहे थे। 2021 अगस्त में जो युवा नौकरी के योग्य थे में से 33 प्रतिशत बेरोज़गार थे।

वार्षिक ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार 2021 में भूख के मामले में भारत 116 देशों 101 रहा है। 2020 में हम 94 नम्बर पर थे। अर्थात् हम और नीचे खिसक गए हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार जैसे पड़ोसी भी हमसे बेहतर हैं। कहा जाएगा कि हमारे आकार और जनसंख्या को देखते हुए यहां चुनौती अधिक है, पर सुपर पॉवर होने का दावा भी तो हम ही करते हैं। अनाज की यहां कमी नहीं, पर सही वितरण और खरीदने की क्षमता की समस्या है। बच्चों में कुपोषण की बहुत बड़ी समस्या है। नवजात में मौत की दर यहां भयानक है।

2021 में पहली बार हमारी प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश से कम हो गई है। 2014 में हम उनसे 50 प्रतिशत आगे थे अब वह आगे निकल गए हैं। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का ताज चीन के कारोबारी जैक मा से छीन कर मुकेश अंबानी सबसे धनी बन गए हैं। फोर्ब्स की 2021 की सूचि में एशिया में मुकेश अंबानी के बाद दूसरी नेबर पर गौतम अडानी हैं। मुकेश अंबानी दुनिया में 10वीं नंबर के रईस हैं। गौतम अडानी 24वें नंबर पर हैं। दुनिया में अरबपतियों की संख्या में भारत तीसरे नंबर पर है। हमसे आगे केवल अमेरिका और चीन है। ब्लूमबर्ग बिलिनियर इंडेक्स के अनुसार दौलत बढ़ाने में हमारे अडानी जी दुनिया में सबसे तेज़ हैं। वह इस मामले में मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार उनकी सम्पत्ति में रोज़ाना 2000 करोड़ की बढ़ोत्तरी देखी गई है।

1980 के बाद उदारीकरण के दौर के कारण भारत ने प्रगति की है। पर हमारे यहां अंतहीन गरीबी और अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई बताती है कि उदारीकरण का फल अधिकतर एकतरफा रहा है। कुछ अर्थशास्त्रियों और विशेष तौर पर अंग्रेजी मीडिया के अभियान के कारण बहुत अधिक जोर 'रिफार्म' पर दिया जा रहा है, पर अगर यह वास्तव में सुधार है तो करोड़ों ग़रीबी मेंइस तरह क्यों लथपथ हैं? 'रिफार्म' शब्द का इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है ताकि कोई विरोध न कर सके। इस तरफ धकेलने में कई

बाक़ी पेज 11 पर

देश के सबसे अमीर 98 लोगों के पास 55.5 करोड़ उनके ग़रीब देशवासियों के बराबर दौलत है जो 49 लाख करोड़ रुपए बनती है। इन 98 लोगों की दौलत भारत सरकार के बजट का 41 प्रतिशत है। पीईडब्लयू की रिसर्च के अनुसार पिछले वर्ष देश के मिडल क्लास की संख्या 3.2 करोड़ कम हुई है पर देश के सुपर रिच के लिए यह महामारी तो छींका टूटा से कम नहीं क्योंकि लॉकडाउन की अवधि में उनकी दौलत 35 प्रतिशत तक बढ़ी है। विश्व असमानता रिपोर्ट के अनुसार यहां अमीरों और ग़रीबों के बीच फासला बढ़ा है और ऊपर के 10 प्रतिशत के पास राष्ट्रीय आय का 57 प्रतिशत है और निचले 50 प्रतिशत के पास इसका केवल 13 प्रतिशत है।

क्या चीन के चंगुल में है पाकिस्तान

आर॰ डोगरा

भारत में इन दिनों पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का खूब चर्चा है। संसद के भीतर और बाहर, सभी जगह इस पर बातें हो रही हैं। इन दोनों देशों में हमेशा से ऐसी मित्रता नहीं थी, बल्कि शुरू शुरू में तो उनमें ख़ासा मनमुटाव था। इस बात के संकेत दो घटनाओं से मिलते हैं। पहली घटना 1950 के दशक की है, जब पाकिस्तान दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन (सिएटो) और केन्द्रीय संधि संगठन (सेंटो) का सदस्य बना, जबकि ये दोनों संगठन कम्युनिस्ट शासन के ख़िलाफ़ थे, यानि चीन और रूस (तब सोवियत संघ) के ख़िलाफ। इसी तरह एक अन्य घटनाक्रम में, जो उसी दशक का है, पाकिस्तान ने तिब्बती विद्रोहियों की मदद करने के लिए अमेरिका को अपना एयरबेस इस्तेमाल करने दिया था। तिब्बती अपनी आज़ादी के लिए चीर से लड़ रहे थे। ज़ाहिर है उस दौर में चीन पाकिस्तान को संदेह की नज़रों से देखता था, क्योंकि उसके मुताबिक वह अमेरिकी खेमे में था।

हालांकि, इस मित्रता की चर्चा करते हुए हम हाल-फिलहाल के इतिहास को भी भूल जाते हैं। कारगिल युद्ध के समय चीन ने पाकिस्तान से नियंत्रण रेखा का सम्मान करने को कहा था। अगर कुछ और पीछे जाए तो 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सफल चीन यात्रा में ही वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर शांति बनाने को लेकर सहमति बनी थी, जो कम से कम 2013 तक तो चली। तब यह भी समझौता हुआ था कि एलएसी के तनाव को दरकिनार करते हुए दोनों देश द्विपक्षीय रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे।

तब आख़िर चीन और पाकिस्तान इतिने करीब कैसे आए? दरअसल 1971 में अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने पाकिस्तान का दौरा किया और वहां से वह बीजिंग गए थे, इसके अगले ही वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन का चीन दौरा हुआ। इसके दो संकेत मिले। पहला, पाकिस्तान को लगा कि अगर चीन के साथ उसके रिश्ते मज़बूत होते हैं तो अमेरिका को कोई एतराज़ नहीं होगा और दूसरा, चीन को महसूस हुआ कि पाकिस्तान की मध्यस्थता से वाशिंगटन उसके करीब आया है और उसके यहां विदेशी निवेश की राह खुली है। फिर भी, चीन पाकिस्तान इतने मित्रवत नहीं है, जितनी चर्चा हो रही है। यदि दोनों के दिल एक होते, तो पाकिस्तान को बीजिंग से कोई अन्य राहतें मिल सकती थीं। जैसे, दो वर्ष पहले एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानि एफएटीएफ द्वारा 'ग्रे सूचि' में डाले जाने के ख़िलाफ़ जब पाकिस्तान हाथ-पांव मार रहा था, तब एफएटीएफ का अध्यक्ष चीन ही था। उसने उसके प्रति कोई दरियादिली नहीं दिखाई। इसी तरह, 2020 के आख़िर में विदेशी मुद्रा भंडार की कमी के कारण जब पाकिस्तान को कर्ज़माफी नहीं मिल रही थी, तब वह चीन की ओर मुड़ा था, पर वहां से भी उसे टका सा जवाब मिला।

साफ है, इस्लामाबाद के साथ दोस्ती में चीन अपना स्वार्थ देखता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के जिन गिने-चुने थर्मल पॉवर प्लांट में उसने निवेश किए हैं, उसमें एक शर्त यह भी है कि इन संयंत्रों से 18 प्रतिशत मुनाफ़ा चीन को मिलेगा, बेशक इनसे पाकिस्तान को नाममात्र की कमाई हो। यही नहीं, 2013 में आर्थिक गलियारे-सीपीईसी में चीन ने 60 अरब डॉलर निवेश का वादा किया था, पर अभी तक उसने 25 अरब डॉलर की रक़म ही जारी की है, जिससे सड़कें और बिजली संयंत्र बने हैं। मगर इसका कोई ख़ास फायदा पाकिस्तान को नहीं होने वाला, क्योंकि इन संयंत्रों से पैदा होने वाली बिजली व्यावसायिक उपयोग में नहीं लाई जाएगी और सड़कों का लाभ तभी मिलता, जब आसपास उद्योग हों और पाकिस्तान में इनका अभाव है इसलिए यह कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि पाकिस्तान अपनी ग़लतियों और नासमझी से चीनी कर्ज़ के जाल में फंसता जा रहा है।

स्थिति यह है कि वर्ष 2013 में पाकिस्तान पर कुल वैश्विक कर्ज़ 44 अरब डॉलर था, जिसमें करीब चार अरब डॉलर (नौ प्रतिशत) चीन का कर्ज़ था। वर्ष 2021 तक उसका कुल वैश्विक कर्ज़ 90 अरब डॉलर हो गया है, जिसमें अकेले चीन का हिस्सा करीब 24 अरब डॉलर, यानि 27 फीसदी है। ज़ाहिर है, जब कोई देश कर्ज़ देता है, तब वह अपने हिसाब से अंकुश भी लगाता है। चीन भी पाकिस्तान पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। मुश्किल यह यह है कि प्रधानमंत्री इमरान ख़ान बड़बोलेपन के शिकार हैं। वह इस वादे के साथ सत्ता में आए थे कि पाकिस्तान दुनिया के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। मगर वर्ष 2018 में बहुत चिरौरी करने पर उन्हें सऊदी अरब से तीन अरब डॉलर का अल्पकालिक कर्ज़ मिला और जब इसे चुकाने की बारी आई, तब वह चीन के दरवाज़े जा पहुंचे। इसके तीन वर्ष बाद, 2021 में उन्होंने पाकिस्तान की ख़राब आर्थिक सेहत का सार्वजनिक रोना रोया। ऐसे बयानों से विदेशी निवेशक हतोत्साहित होते हैं। फिर, कर्ज़ देने वाले देश को यदि आपकी माली हालत का पता चल जाए, तो वह धन देने से पहले कई तरह के फायदे उठाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है। इमरान ख़ान इस समय चीन के दौरे पर हैं और पाकिस्तानी मीडिया का अनुमान है कि वह वहां छह अरब डॉलर का कर्ज़ लेने गए हैं, क्योंकि मुल्क का विदेशी मुद्रा भंडार भंडार अब इतना ही बचा है कि तीन माह की ज़रूरतें पूरी हो सके। उधर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसे हर हाल में 21 अरब डॉलर करने को कहा है।

पाकिस्तान का यह आर्थिक जंजाल सीधे तौर पर भारत को लाभ नहीं पहुंचाएगा। उसकी अर्थव्यवस्था बेशक डूब जाए, लेकिन उसका रुख़ शायद ही बदलेगा। अस्थिरता तो उसका

बाक़ी पेज 11 पर

दिल्ली को अभी मास्टर प्लान 2041 के लिए करना होगा इतज़ार

पिछले दिनों ख़बर आई थी कि दिल्ली को मास्टर प्लान जल्द मिलने वाला है, पर अभी दिल्लीवालों को इसके लिए और इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि मास्टर प्लान 2021 के समाप्त होने के बाद तक नया मास्टर प्लान 2041 लागू नहीं हो सका है। बताया जाता है कि तकनीकी पहलुओं के कारण अभी मास्टर प्लान 2041 को लागू करने में थोड़ा वक़्त और लगेगा। संभावना जताई जा रही है कि इस प्रक्रिया में करीब चार माह का समय लग सकता है, ऐसे में नया मास्टर प्लान अगस्त में ही लागू होने की चर्चा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक नया मास्टर प्लान लागू नहीं होगा, तब तक पुराने मास्टर प्लान को ही इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन वह कई मायनों में न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि बीस वर्ष को ध्यान में रखकर नियम बनाए गए थे, अब बदलते परिवेश में वे नियम और निर्माण तकनीक में काफी अंतर हो गया है। दरअसल कई करोड़ रुपये का बजट मास्टर प्लान 2041 की तैयारियों और इस पर होने वाली चर्चाओं के लिए रखा गया था। जिसके बाद 2021 में पूरे वर्ष ऑन लाइन व अन्य तरीक़े से बैठक व जनता की राय मास्टर प्लान 2041 के संदर्भ में की गई। लोगों एवं विभिन्न समूहों व विशेषज्ञों से मिली राय के आधार पर प्रस्ताव को केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामला मंत्रालय के समक्ष भेजा गया। जहां से पहले चरण की सहमति डीडीए व एनआईयूए को प्राप्त हो गई। सितंबर में इस प्रक्रिया के पूरा होने के साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों ने दिसंबर 2021 के अंत तक नए मास्टर पलान को अन्तिम रूप देने का दावा भी किया था। लेकिन 2022 में करीब डेढ़ माह गुज़रने के बावजूद अब तक यह दावा केवल कोरा दावा ही है।

इससे पहले ख़बरें थी कि दो माह में राजधानी को अगले 20 वर्ष का मास्टर प्लान (एमपीडी 2041) मिल जाएगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) इस प्लान के ड्राफ्ट पर मिले 33 हजार आपत्तियों एवं सुझावों पर जन सुनवाई पूरी करने के बाद उनका समावेश करने में जुटा है। एक डेढ़ माह में प्लान का फाइनल ड्राफ्ट स्वीकृति के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में होने वाली बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। इसके बाद अधि सूचित करने के लिए केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय को भेजा जाएगा। एमपीडी 2021 की अवधि दिसंबर में ही खत्म हो चुकी है।

डीडीए के एक अधिकारी ने कहा कि फिलहाल प्रक्रिया जारी है कुछ तकनीकी कारणों से नए मास्टर प्लान 2041 को लागू करने में विलंब हुआ है। अभी लगभग दो से तीन माह या अधिक समय भी लग सकता है जिसके बाद इसे औपचारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया जाएगा।□□

यमुना का प्रदूषण कम करेगा मजलिस पार्क का एसटीपी

यमुना में मार्च तक करीब 318 एमएलडी (मेगामीटर प्रतिदिन) गंदा पानी गिरने से रुकेगा। मजलिस पार्क में बन रहे कोरोनेशन पीलर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट फरवरी के अंत तक पूरा होने की संभावना है, जिसके बाद यह संभव हो पाएगा, जिसके बाद यह संभव हो पाएगा। इस पानी को दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकेगा।

इस एसटीपी के चालू होने के बाद यमुना में रोज़ाना गिरने वाले 30 किलो कार्बनिक प्रदूषक (आर्गेनिक पॉल्युटेंट) और 50 किलो ठोस प्रदूषक (सॉलिड लोड) का भार भी कम होगा। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली सरकार की फरवरी 2025 तक यमुना को साफ करने की योजना है। इसके तहत अलग अलग 12 एसटीपी पर काम हो रहा है। ओखला में सबसे बड़ा एसटीपी बनाया जा रहा है, जिसकी क्षमता 564 एमएलडी है। दिल्ली में रोज़ाना कुल करीब 3273 एमएलडी सीवरेज निकलता हे।

दिल्ली के अलग-अलग एसटीपी 2340 एमएलडी सीवरेज को साफ कर रहे हैं। वैसे, एसटीपी संयंत्रों की क्षमता तकरीबन 2634 एमएलडी सीवरेज साफ करने की है।

दिल्ली को वर्ष 2031 तक 1500 एमजीडी पानी की ज़रूरत पड़ेगी। कॉलोनियों में पानी की आपूर्ति पाइप लाइन से पहुंचाने का प्रयास तेज़ी से जारी है। वर्तमान में पीक ऑवर में अधिकतम करीब 1200 एमजीडी की मांग रहती है। दिल्ली जल बोर्ड करीब 935 एमजीडी पानी की सप्लाई करता है।

जानकारों के मुताबिक, यमुना में रोजाना 933 एमएलडी सीवरेज बिना साफ हुए गिरता है। कोरोनेशन एसटीपी रोज़ाना करीब 31 करोड़ 8 लाख लीटर पानी साफ करेगा।

जानकारी के मुताबिक इस योजना को बनाने की अनुमानित रकम तकरीबन 515 करोड़ रुपये है। यमुना को साफ करने के लिए दिल्ली में 1384.50 एमएलडी की कुल 12 परियोजनाएं चल रही हैं। इसके अलावा पानी की गुणवत्ता जांच के लिए नौ प्रयोशालाएं चौबीस घंटे काम कर रही हैं।

संपादकीय

शांति मिशन

ग़लतफहमियों को दूर करने के लिए

इस्लाम का परिचय समय की ज़रूरत

भारत विश्व के उन ख़ुशनसीब देशों में से एक है जहां एक बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान आबाद हैं। यह मुसलमान बहुसंख्यक तो नहीं है लेकिन वह देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक (20 करोड़ के लगभग) होने की वजह से देश की दूसरी बड़ी बहुसंख्यक ज़रूर कहे जा सकते हैं। 1947 की मारकाट बंटवारे के बाद देश को आज़ादी मिली और यह कहना अतिश्योक्ति न होगा कि इस बंटवारे से सब से अधिक भारतीय मुसलमान ही प्रभावित हुए, इस बंटवारे की प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीय मुसलमानों को भारी अनिश्चितता और दुश्मनी से दोचार होना पड़ा और फिर क़त्ल व गारतगरी और बेऐतबारी की पीड़ा झेलने वाले भारतीय मुसलमानों के घावों पर नमक छिड़कते हुए बंटवारे का ज़िम्मेदार भी बना दिया गया, जबकि हक़ीक़त यह है कि भारतीय मुसलमानों ने हर तरह का दबाव बर्दाश्त करते हुए अपने प्यारे देश में ही रहने को प्राथमिकता दी थी। बंटवारे के बाद के सालों में भारत के मुसलमानों को पक्षपात मुश्किलात और नासमझियों के भंवर में फंसाने की कोशिशें की गयीं। अल्लाह की तौफीक़ से उन्होंने बहुत सब्र से उन चुनौतियों का मुकाबला किया। वह हमारी मिल्ली तारीख का एक रौशन बाब है। इस नफ़रत भरे माहौल में भारतीय मुसलमानों ने न तो मायूसी दिखाई और न नाउम्मीदी को अपने दिल में कोई जगह दी और न उन्होंने हिंसा की राह चुनी, उन्होंने अपने भरोसे को ज़िन्दा किया और देश के अच्छे नागरिक की हैसियत से ज़िन्दगी जीने का मज़बूत इरादा किया। आज स्वतंत्र भारत में मुसलमानों की संख्या बीस करोड़ के आंकड़े को छू रही है। यह संख्या इंडोनेशिया के बाद सबसे अधिक है, फिर भी यह बात अफसोस के साथ नोट की जाएगी कि आज भी भारत में मुसलमान काफी बुरे हालात से दोचार हैं, जान व माल और इज्ज़त व आबरू के साथ-साथ मुसलमानों के ईमान और अक़ीदे और उनकी धार्मिक पहचान हर समय हमलों के निशाने पर है। आज उन पर आतंकवादी का ढप्पा लगाकर उन के दीनी संस्थाओं को आतंकवाद की फैक्ट्री कहा जा रहा है। मुस्लिम हिन्दुस्तानी बादशाहों के नाम पर उन्हें आक्रमणकारी, अपहरणकर्ता और विदेशी क़रार देने की कोशिश की जा रही है।

क़ुरआन करीम जो पूरी इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा है उसे क़त्लोग़ारत का निमंत्रणदाता बताकर उस पर पाबंदी लगाने की मांग की जा रही है। मुसलमानों के पर्सनल लॉ सरकार के निशाने पर हैं। एक सिविल कोड का फितना रह-रहकर सर उठा रहा है। इस्लाम के बारे में झूठ फैलाने के लिए हमारे बुद्धिजीवी वतनी भाईयों में होड़ लगी हुई है, साम्प्रदायिक नफ़रत का एक तूफान है, जो सरकारी संरक्षण में जारी है।

भारत में मुस्लिम दुश्मन और साम्प्रदायिक तत्व यूरोप के पक्षपाती लेखकों की कुछ पुस्तकों के हवाले से यह साबित करने की कोशिश में लगे हैं और देश की तमाम मीडिया का प्रयोग करते हुए देश के भोले-भाले बहुसंख्यक को यह बताने में अपनी जान लगा रहे हैं कि हिन्दुस्तान में मुसलमानों की आमद क्रूरता की पहचान है जबकि तारीख़ी सच्चाई यह है कि मुसलमान यहां सबसे पहले व्यापारी के तौर पर आए उन्होंने कारोबार में इस्लामी सिद्धांत अपनाए, नर्मी और विनम्र स्वभाव को अपना नियम, काएदा बनाया, उनकी इन आदतों और तर्जे अमल से भारत की जनता प्रभावित हुई और वह इस्लाम की ओर झुके इसलिए कि यहां के लोगों ने इन व्यापारियों और मुबल्लिग़ों में जो सिफाते हमीदा अपनी आंखों से देखीं वह उनके लिए उनके माहौल में अनमोल थीं फिर जो मुसलमान ताजिर और मुबल्लिग़ भारत आए तो वह क़ुरआन व हदीस की उन आयात व रिवायात के अमीन बनकर आए जो मज़ाहिबे आलम वजूदे बाहम और सब्र व तहम्मुल का पाठ पढ़ाती हैं। इस्लाम बुनियादी तौर पर धार्मिक विविधता को मानता है। अल्लाह का फरमान है : दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है (सूरह बक़रा), इस्लाम अपने मानने वालों को यह कहने पर आमादा करता है कि ''तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ और मेरा दीन मेरे साथ'' (सूरह काफिरून) इस सब के बावजूद भी इस्लाम के तअल्लुक़ से ग़लतफहमियों का एक भारी तूफान है जिसे भेदभाव, दुश्मनी, तंगनज़री के अलावा और क्या कहा जा सकता है, हालांकि यहां मुसलमान चाहे किसी किसी रूप में भी आए हैं उन्होंने इस देश के अलग-अलग तरीक़ों से चार चाँद ही लगाये हैं।

इस सच्चाई से हम मुंह नहीं छुपा सकते कि आज इस्लाम और मुसलमानों के विरुद्ध जिस बड़े स्तर पर इस्लाम दुश्मन ताक़तें झूठ और काल्पनिक ताने-बाने बुन रही हैं उसको दूर करने और हक़ को ज़ाहिर और बातिल के तोड़ की कोशिशें हमारे यहां अभी तक न होने के बराबर हैं, जब इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई हवा का झोंका आता है तो हम बचाव की पोज़िशन अपनाते हुए केवल यह कहकर चुप हो जाते हैं कि :- ''फूकों से यह चिराग़ बुझाया न जाएगा।''

जबकि हमें इससे बहुत आगे जाकर उन ग़लतफहमियों को दूर करने की ज़िम्मेदारी को निभाने की आवश्यकता है। हमारे अलावा आज बहुत से लोग मज़ाहिब के बारे में बहुत कुछ लिख रहे हैं। तुलनात्मक अध्ययन भी हो रहे हैं, रिसर्च सेंटर भी बने हैं, उनमें शोध का कार्य भी हो रहा है और खुद वतनी भाई उसका एतराफ भी कर रहे हैं कि अगर हक़ीक़ी मायने में कोई मज़हब है तो वह ''इस्लाम'' है और इस साइंटिफिक युग में भी वह अपनी अहमियत, उपयोगिता और ज़रूरत को मनवा रहा है, अभी कुछ वर्ष पहले हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक और बुद्धिजीवी श्री राजेन्द्र नारायण लाल की एक रिसर्चर किताब सामने आई थी जिसका नाम ''इस्लाम एक स्वयं शुद्ध ईश्वरी जीवी व्यवस्था है'' श्री राजेन्द्र नारायण लाल ने अपनी इस पुस्तक में इस्लाम की प्रस्तावना कराते हुए जो लिखा है उसका एक चयन हम ''तामीरे हयात'', लखनऊ में प्रकाशित हुआ, जो हम अपने पाठकों के लिए पेश कर रहे हैं, वह लिखते हैं :

इस्लाम के लफ्ज़ी मायनी अल्लाह की मर्ज़ी के आगे पूरी तरह सिर झुका देना, यानि पूरी तरह अल्लाह का मतीअ और आज्ञाकारी हो जाना, इस तरह शुरू में ही इस्लाम तौहीद का मज़हर हो जाता है, इस्लाम 'मोहम्मदडनइज़्म' नहीं है, अल्लाह का उतारा हुआ दीन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लललाहो अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया थे, इस्लाम के ख़िलाफ़ हिन्दू धर्म का कोई ठोस सबूत नहीं है, बौद्ध धर्म और ईसाइयत केवल संस्थापकों से सम्पर्क को साबित करते हैं और विस्तार का नेतृत्व नहीं करते, इसके बरअक्स इस्लाम विश्व के अलग अलग भागों में हज़रत मुहम्मद सल्ल॰ से पहले भेजे हुए तमाम रसूलों और नबियों का सम्मान करता है, उस का कहना है कि बुनियादी तौर पर तमाम धर्म एक ही थे, समय बीतने के साथ-साथ जब उसमें बाहरी मामले दाख़िल हो गए, उनमें बदलाव किया गया और वाक़ई अहकामे इलाहिया से भटक गए तो अल्लाह ने वाक़ई क़तई शक्ल में रसूलुल्लाह सल्ल॰ के लिए क़ुरआन उतारा, ''ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह'' दीने इस्लाम का कलमा है, इस्लाम के पांच बुनियादी स्तंभ है : कलिमा शहादत, नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात।

इस्लाम ने इन सिद्धांतों को अधिक बामक़सद और प्रभावशाली बनाया और समाज के लिए आश्चर्यजनक तौर पर लाभदायक बनाया है, सबसे अधिक प्रसन्नता की बात यह है कि इस्लाम में तौहीद को छोड़कर दूसरे चार उसूलों में ग़ैर मामूली हालात के अनुसार विशेष छूट दी गयी है, तौहीद तो दिल, दिमाग़ और रूह से, सबसे शक्तिशाली अल्लाह पर ईमान से तआल्लुक़ रखती है इसलिए इसमें रियायत और छूट का सवाल ही नहीं है, इसमें छूट तो शिर्क है, दूसरी मज़ाहिब में एकेश्वरवार (तौहीद) में छूट और घटाने बढ़ाने की ही वजह से करप्शन आया, इस्लाम हर शिर्क को शिर्क ही समझता है, इस्लाम ने तौहीद को सबसे महफूज़ रखा, यह इस्लाम की सबसे बड़ी ख़ूबी है।

श्री राजेन्द्र नारायण लाल ने विश्व के चार धर्मों हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया है। उनकी पैदाइश राजस्थान में हुई, शिक्षा उन्होंने काशी में प्राप्त की उनका धर्म तुलनात्मक अध्ययन विस्तृत है और अपने भरपूर अध्ययन की रोशनी में उन्होंने इस्लाम के संबंध से अपने-अपने इन कीमती राय का इज़हार किया है। आज के हालात में इस बात की बहुत ज़रूरत है कि जहां ऐसे लेखों और पुस्तकों को आम किया जाए और वतनी भाईयों में उनको फैलाया जाए वहीं ख़ालिस धार्मिक व इल्मी भावना से बिला इम्तियाज़े मसलक, सम्प्रदाय एक ऐसी संस्था वजूद में लाया जाए जो इस्लाम की तफहीम व तशरीह का स्वयं राष्ट्र बंधू की ज़ुबान में कार्य करें, साथ ही अपने अमल और किरदार से इस्लाम और मुसलमानों की नाफइय्यत और इस्लाम की खूबियों को उजागर किया जाए, इसके लिए ईसार और कुर्बानी के साथ इल्मी व अमली संघर्ष राष्ट्र बंधुओं के सालेह मिजाज़ अफराद से राब्ता उन तक इस्लामी तालीमी तालीमात और नबी सल्ल॰ की सीरत को पहुंचाना होगा। याद रखिए इस्लाम अल्लाह का अताकरदा एक ऐसा दीन है जिससे पूरी इंसानियत की फलाह के लिए है, इस्लाम के ज़रिए उसने इंसानों को आला मक़ाम से नवाज़ा और पूरी क़ायनात को उनके ताबेअ कर दिया है और इस तरह इस्लाम ने इस कायनात में इंसानी वक़ार का बोलबाला कर दिया है जिसकी बक़ा व तहफ्फुज़ की ज़िम्मेदारी खुद हम पर है।□□

फ़रिश्ते को नबी क्यों नहीं बनाया गया?

दुनिया में किसी फ़रिश्ते को नबी बना कर नहीं भेजा गया क्योंकि वह हमारे लिए नमूना नहीं बन सकता, इस लिए कि वह तो चौबीस घंटे, महीनों और सालों इबादत में मशग़ूल रहेगा और वह थकेगा भी नहीं इसके बावुजूद वह अगर बुराई से बचेगा और अच्छाई करेगा तो सवाब मिलेगा, यही इम्तेहान का मतलब है, तो इसी ग़र्ज़ से अल्लाह तआला ने इंसानों ही में से अंबिया अलैहिमुस्सलाम को नमूना बना कर भेजा। पहले यह होता था कि अंबिया ख़ास क़ौमों की तरफ़ तशरीफ़ लाते थे, बयक वक़्त कई कई नबी होते थे, जब क़ौम में बिगाड़ होने लगता तो दूसरा आ जाता लेकिन हमारे आक़ा व मौला हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अल्लाह तआला ने क़यामत तक के लिए नबी बनाकर मबऊस फ़रमाया, मश्रिक़ व मग़्रिब के लिए आप को नबी बनाया, जिन्नात और इंसानों के लिए आप को नबी बनाया, तमाम आलम के लिए आप ही को नुबुव्वत अता फ़रमाई क्योंकि अब कोई नया नबी दुनिया में आने वाला नहीं है, आप पर दीन को मुकम्मल कर दिया, अब आप के दीन के अलावा कोई चीज़ ज़रिया-ए-निजात नहीं है, और इंसानियत को इज़्ज़त नहीं मिल सकती जब तक कि वह पैग़म्बर के तरीक़े पर न चले, न दुनिया में कामियाबी मिलेगी न आख़िरत में कामियाबी मिलेगी, यही दीने मुहम्मदी ज़िंदगी का सब से बड़ा सरमाया है, इस लिए हर मुसलमान की यह ज़िम्मेदारी है कि वह पैग़म्बर की सीरत से अपने आपको जोड़ कर रखे, जितना सीरत से क़रीब होता जायेगा, उतना ही पैग़म्बर से क़रीब हो जायेगा।

जगहों के नाम बदलना राष्ट्रवाद नहीं

इरफान हबीब

पद्म भूषण से सम्मानित विख्यात इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग में एमेरिट्स प्रफेसर हैं। भारत के मध्यकलीन इतिहास, प्राचीन भारत के ऐतिहासिक भूगोल, भारतीय प्रौद्योगिकी के इतिहास, मध्यकालीन प्रशासनिक और आर्थिक इतिहास, उपनिवेशवाद और उसके प्रभावों पर उनका व्यापक कार्य है। 'एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुग़ल इंडिया', 'एन एटलस ऑफ द मुग़ल एंपायर', 'एसेज इन इंडियन हिस्ट्री : टुवर्ड्स ए मार्कसिस्ट परसेप्शन, कैंब्रिज इकॉनामिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया-खंड-1, यूनेस्को की हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी आदि उनकी चर्चित किताबें हैं। इन दिनों इतिहास से राजनीति की दशा और दिशा बदलने के आरोप लग रहे हैं। यहां प्रस्तुत है इरफान हबीब से हुई एक लंबी बातचीत के मुख्य अंश:-

सवाल:- आप मुग़ल राजकुमार दारा शिकोह की कब्र खोजने में जुटे थे। आख़िर कहां है उनकी कब्र?

जवाब:- हुमायं के मकबरे के परिसर में कुछ कब्रों के नाम प्रमाणित है। माना जाता है कि उसी परिसर में मुग़ल सम्राट शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह को दफ़नाया गया था। वहां अन्य मुग़ल राजकुमारों की कब्रें भी हैं लेकिन यह प्रमाणित नहीं होता कि दारा शिकोह की कब्र कौन सी है।

सवाल:- पृथ्वीराज चौहान के पोते अनंगपाल द्वितीय को लेकर दिल्ली में सरकार एक संग्रहालय बना रही है। कहा जा रहा है कि इससे पहले इन हिन्दू राजाओं के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। आप इसे कैसे देखते हैं?

जवाब:- ऐतिहासिक दस्तावेज़ों में 'तबक़ात-ए-नसीरी' नामक एक पुस्तक फारसी भाषा में लिखी हुई है, जिसे मिनहाज-उस-सिराज ने लिखा है। वह मध्य एशिया का निवासी था और सुल्तान इल्तुमिश के दौर में भारत आया था। 'तबकात-उस-नसीरी' और कुछ अन्य शिलालेखों से हमें दिल्ली सल्तनत और अन्य जानकारियां मिलती हैं। उसके अलावा चाहमान या चौहान शासकों के बारे में बहुत कम जानकारी मिल पाती है। इस आधार पर हम उनके शासन की एक प्रमाणिक तस्वीर नहीं बन सकते। कल्पना के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

सवाल:- औरंगज़ेब, अकबर और टीपू सुल्तान की चर्चा समसायिक राजनीति को लेकर हो रही है। दिल्ली में औरंगज़ेब रोड का नाम भी बदला गया। इस मामले में क्या सोच है आपकी?

जवाब:- औरंगज़ेब ने धार्मिक भेदभाव की नीति का पालन किया, लेकिन औरंगज़ेब रोड का नाम बदलने का कोई औचित्य नहीं था, जो कि नब्बे सालों से था। न ही उत्तर प्रदेश में पहले से स्थापित स्थानों के नाम बदलने का कोई अच्छा कारण रहा है।

सवाल:- एक वर्ग मानता है कि वामपंथी इतिहासकारों ने भारत का इतिहास सही ढंग से नहीं लिखा?

जवाब:- ऊँच-नीच के विचार और निम्न वर्गों के उत्पीड़न के कुकृत्यों ने हमारे इतिहास को उतना ही गंदा किया है, जितना अन्य देशों में, चाहे आप प्राचीन भारत को लें या मुग़ल भारत को। इधर, अब 'राष्ट्रवादी' इतिहास के नाम पर पौराणिक कथाओं/दानवों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इतिहास सिर्फ 'इतिहास' है, इसे साधारण बनावटीपन से राष्ट्रवादी या हिन्दुत्व से आच्छादित या किसी बात के लिए इस्लामी नहीं किया जा सकता।

सवाल:-एक वर्ग को आरएसएस से समस्या क्यों है?

जवाब:- आरएसएस का जन्म सांप्रदायिक हिंसा में तथाकथित हिन्दू पक्ष लेने के मूल नारे से हुआ था। इसने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया। गोलवलकर ने 1938 में घोषणा की थी कि मुसलमान भारत के नागरिक नहीं हो सकते, जिनकी पुस्तक 'वी ऑर अवर नेशनहुड डिफाइंड' को पढ़ा जा सकता है।

सवाल:- आप पंडित जवाहर लाल नेहरू से मिले थे? शायद आपको सरकारी फेलोशिप मिलने वाली थी, लेकिन उसका विरोध हो रहा था। आपको यह फेलोशिप आख़िर कैसे मिली? तब आपको सरकार के विरोधी खेमे के लेखक भी माना जाता था। क्या हुआ था..?

जवाब:- पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल अलग तरह के प्रधानमंत्री थे। यह बात सन 1955 की है। मैं सुबह-सुबह प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचा तो अंदर केवल उनका सचिव था। उनके कार्यालय में कोई गार्ड या चपरासी नहीं था। तब मैं अलीगढ़ में इतिहास का व्याख्याता नियुक्त हुआ था। मेरे लेख सरकार के विरुद्ध होते थे, इस कारण गृह मंत्रालय मुझे पासपोर्ट नहीं रहा था। इसके लिए मैंने पंडित जवाहर लाल नेहरू जी को एक पत्र लिखा था। नेहरू जी ने अपने विरोधियों की आपत्तियों को नज़र अंदाज़ कर मुझे फेलोशिप देने की सिफारिश की थी। मेरी उनसे मुलाक़ात हुई, जिसके बाद मुझे पासपोर्ट मिला। एक उदार और विस्तृत सोच वाले प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू जी!

सवाल:- हम देखते हैं कि कुछ साहित्य को ही इतिहास मानने लगते हैं। एक इतिहासकार की दृष्टि से आप इसे कैसे देखते हैं? मुग़ल इतिहास में आपकी रुचि कैसे विकसित हुई?

जवाब:- इतिहास के अंदर साहित्य का इतिहास भी है, साथ ही विश्वासों और विचारों का इतिहास शामिल है लेकिन यह स्वाभाविक रूप से इससे कहीं अधिक व्यापक है। मेरी रुचि इतिहास में थी और मैं मुग़ल भारत के इतिहास की खोज में गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि भारतीय इतिहास की किसी भी अवधि के मुक़ाबले इस काल खंड में अधिक स्रोत सामग्री है।

सवाल:- आज इतिहास की राजनीति हो रही हैं कई शहरों, रेलवे स्टेशनों आदि के नाम बदले जा रहे हैं। इसके लिए तर्क दिया जाता है कि यह पहले हुई ग़लतियों को ठीक करने के लिए हो रहा है। आप इसे किस तरह से देखते है.?

जवाब:- ऐतिहासिक और परिचित जगहों के नाम बदलना असहिष्णुता का प्रमाण है, इसे राष्ट्रवाद नहीं माना जा सकता।□□

जेएनयू में हुए प्रोटैस्ट मेरे लिए फीडबैक : एम॰ जगदीश कुमार

हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (यूजीसी) को अपना नया चेयरमैन मिला हैं जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) में छह साल तक वाइस चांसलर की ज़िम्मेदारी संभालने के बाद प्रो. एम. जगदीश कुमार को अब यूजीसी चेयरमैन बनाया गया है। जेएनयू वीसी का उनका कार्यकाल विवादों और विरोध प्रदर्शनों से भरा रहा। यूजीसी चेयरमैन के रूप में देशभर की यूनिवर्सिटयों के लिए उनके क्या प्लान हैं, इस पर प्रो. जगदीश कुमार से एक बातचीत हुई, पेश है इस बातचीत के प्रमुख अंश :-

प्रश्न:- अब सबसे पहले आप क्या करने जा रहे है..?

उत्तर:- पहले तो मुझे नेशनल एजूकेशन पॉलिसी (एन.ई.पी.) लागू करानी है। एनईपी 2020 में कोविड के बीच लाँच हुई। हालांकि, इससे हमें इसे समझने का वक़्त मिला और सभी को जागरुक किया जा सका। अब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि एनईपी को सभी हायर एजूकेशनल इंस्टीटयूट में लागू कर सकें। इसमें कई प्रावधान ऐसे हैं, जिनको लेकर यूजीसी को रेग्यलेशंस बनाने की ज़रूरत है ताकि यूनिवर्सिटी/कॉलेज लागू कर पाएं। इस पर हम तेज़ी से काम पूरा करेंगे हमारी प्राथमिकता है कि सभी यूनिवर्सिटी को मल्टी डिसिप्लिनरी एजूकेशन के नए कोर्स शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करें।

प्रश्न:- कॉलेजों की अटॉनमी का भी पेच फंसा है। चीज़ें ऑनलाइन की ओर जा रही हैं। इन्हें लेकर क्या करने का रहे हैं?

उत्तर:- कई कॉलेजों को हम अटॉनमी देंगे ताकि वे डिग्री देने वाले कॉलेज बन जाएं। इसके लिए इन्हे नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडटेशन काउंसिल से एक तय ग्रेडिंग हासिल करनी होगी। यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, दो वर्ष में हमारे पास ऐसे कई कॉलेज होंगे। इसके अलावा, ऑनलाइन डिग्री देने के लिए भी हम इंस्टीटयूट को तैयार करेंगे। हम ऑनलाइन एजूकेशन रेग्युलेशंस को सरल बनाने की प्रक्रिया में है। इस पर कमिटी का काम फाइनल स्टेज में हैं। इसके लिए जिन यूनिवर्सिटीज के पास टेक्नोलॉजी और संसाधन नहीं हैं, उनके लिए एजूटेक कंपनियों से बातचीत भी कर रहे हैं।

प्रश्न:- एनईपी के तहत इंस्टिटयूशनल डिवेलपमेंट प्लान के ड्राफ्ट में 50 प्रतिशत कान्ट्रैक्चुअल/विजिटिंग फैकल्टी की बात है। टीचर-छात्र का रेश्यो भी कम किया है। क्या इससे एजूकेशन क्वॉलिटी पर असर नहीं पड़ेगा..?

उत्तर:- हमारे पास काफी परमानेंट पोस्ट्स खाली हैं। ज़्यादातर आईआईटी में 30 प्रतिशत और सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 30 से 40 प्रतिशत पोस्ट ख़ाली हैं। कितनी जल्दी ये पोस्ट्स भरी जा सकती है, यह हाई क्वॉलिटी पीएचडी कैंडिडेट्स के मिलने पर निर्भर करता है। इस वजह से हमें कान्ट्रैक्चुअल फैकल्टी की भी ज़रूरत है। हम ऐसे लोगों से तो इन्हें नहीं भर सकते जो एक क्लास भी ना ले सकें। देश में क्वालिटी पीएचडी छात्रों की संख्या कम है, यह हमारे लिए एक चुनौती है। यूजीसी ने मिनिमम स्टैंडर्ड तय किए हैं, मगर छात्रों को इससे काफी ऊपर जाने की आवश्यकता है। इसके लिए सभी इंस्टिटयूट में रिसर्च सुविधाओं और फंड की भी ज़रूरत है। इसमें हाई क्वालिटी संस्थानों साधारण संस्थानों के साथ अपनी रिसर्च सुविधाएं, महंगे इक्विपमेंट साझा कर मदद कर सकते हैं। आईआईटी, जेएनयू ऐसा करते हैं। टीचर छात्र रेश्यो भी क्वॉलिटी बनाए रखते हुए ही तय किया जाएगा।

प्रश्न:- एनईपी हायर एजूकेशन कमिशन ऑफ इंडिया भी ला रही है। इसमें यूजीसी मर्ज़ हो जाएगा। यूजीसी के रोल में कितना फर्क पड़ेगा?

उत्तर:- एआईसीटीई, यूजीसी जैसे सभी बॉडी इसमें मर्ज़ हो जाएगी। इसके चार पिलर होंगे - एक, इंस्टिटयूट को रेग्युलेट करेगा, दूसरा स्टैंडर्ड सेट करेगा, तीसरा फंडिंग और चौथा एक्रिडिटेशन देगा। यह जब भी होगा, यूजीसी इसके लिए ग्राउंड वर्क पहले ही पूरा करेगी।

प्रश्न:- जेएनयू में आपके कार्यकाल के दौरान कई प्रदर्शन भी हुए। अब आप देशभर की यूनिवर्सिटी संभाल रहे हैं। जेएनयू का अनुभव यूजीसी में कितना काम आएगा..?

उत्तर:- प्रदर्शन एक तरह से फीडबैक होते हैं और यह मुझे जेएनयू में मिलते रहे। इससे मुझे छात्रों की दिक्क़तों को समझने का अवसर मिला और हम जेएनयू में कई नई चीज़ें लाने में भी सफल हुए। हमने वहां इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के स्कूल भी शुरू किए। अगर प्रदर्शन सही तरीक़े से हों, हिंसक न हों, तो उनमें कोई बुराई नहीं है। वे सभी अनुभव हमेशा मददगार रहेंगे।

प्रश्न:- कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर क्या कहेंगे?

उत्तर:-इस परमैं कुछ नहीं कहूंगा। मगर मैं जेएनयू से आया हूं तो यह जरूर कहूंगा कि वहां किसी तरह का ड्रेस कोड नहीं है। कैंपस में कपड़े छात्रों की पसंद, जगह और मौसम के हिसाब से हो सकते हैं।□□

मिज़ान

अवधेश कुमार

दल-बदल के बारे में धारणा बदलने की आवश्यकता

हाल ही में दल-बदल पर आए एक समाचार ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। गोवा में पिछले 05 सालों में विधानसभा के कुल 40 सदस्यों में से 24 ने दल बदला। इस तरह 60 प्रतिशत विधायकों ने उस दल को छोड़कर दूसरे दल का दामन थामा जिनसे वे चुनाव जीते थे। सामान्य तौर पर इस तरह की घटनाएं किसी भी विवेकशील व्यक्ति को विचलित कर सकती हैं। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान हम देख रहे हैं कि किस तरह नेताओं को पार्टी बदलने में हिचक महसूस नहीं होती दिखी।

भारतीय राजनीति में यह दृश्य नया नहीं है जिस पर हम आश्चर्य प्रकट कर सकें। गोवा छोटा राज्य है, इसलिए वहां 60 प्रतिशत विधायकों की बात हमने की लेकिन पूर्वोत्तर में ऐसा लगातार होता है और बनी हुई सरकारें गिरती रही है। दल-बदल की अनेक घटनाओं ने राजनीति को विकृत किया हैं 1980 में भजनलाल जनता पार्टी से 37 विधायकों के साथ कांग्रेस में चले गए और मुख्यमंत्री बनें। उसके पहले इतनी बड़ी संख्या में एक साथ जनप्रतिनिधियों के दल बदलने की घटना नहीं हुई थी। हरियाणा भारत का ऐसा राज्य है जहां दल- बदल ने लगातार सत्ता और राजनीति को विकृत किया है।

यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर दल-बदल की ऐसी बड़ी घटनाएं नहीं हुई लेकिन गठबंधन सरकारों के दौर में किसी सरकार को समर्थन देकर वापस लेने तथा दूसरे गठबंधन को समर्थन देने की घटनाएं हुई हैं। 1979 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार को समर्थन दिया और कुछ ही दिनों में उसे वापस ले लिया। इससे समय पूर्व आम चुनाव में जाने की विवशता देश में पहली बार उत्पन्न हुई। 1971 में इंदिरा गांधी ने एक वर्ष पूर्व चुनाव कराने का फैसला अपनी राजनीति के तहत किया था। तब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। दूसरी बार विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार को समर्थन देने वाली भाजपा ने 1990 में हाथ खींचा तथा उसके बाद चन्द्रशेखर सरकार को समर्थन देकर राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने 100 दिन में सरकार को गिरा दिया। इस तरह देश को मजबूरी में दूसरी बार आम चुनाव में समय से पूर्व जाना पड़ा।

1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार को समर्थन देने वाली कांग्रेस ने दो दो बार हाथा खिंचा। पहली बार तो देवेगौड़ा की जगह इन्द्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बना देने के कारण सरकार बच गई लेकिन दूसरी बार नहीं बची। देश को आम चुनाव में जाना पड़ा। ऐसे ही अन्नाद्रमुक ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से 1999 में समर्थन वापस ले लिया और देश को चुनाव में जाना पड़ा।

इस तरह देखें तो राजनीति में दल बदल के सकारात्मक परिणाम सामान्य तौर पर दिखाई नहीं देंगे। यह सच भी है कि भारत में ज़्यादातर दल-बदल या समर्थन वापसी वैचारिक प्रतिबद्धताओं की जगह संकुचित स्वार्थों या फिर राजनीति प्रतिशोध के भाव में उत्पन्न हुए। लेकिन क्या वाक़ई दल-बदल की हमेशा खलनायक के रूप में ही देखा जाए? जिन लोगों ने 1977 में इंदिरा गांधी से विद्रोह कर कांग्रेस छोड़ा क्या उन्हें भी हम इसी तरह दल-बदलू मान सकते हैं? भाजपा अयोध्या आंदोलन में सक्रिय थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा उनके रणनीतिकारों को पता था। लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को रोकने तथा उन्हें गिरफ्तार करने के बाद भाजपा के पास विकल्प क्या था? वह उसकी विचारधारा का प्रश्न था।

इसी तरह अगर राजीव गांधी की हत्या में द्रमुक को लेकर संदेश था तो गुजराल सरकार से समर्थन वापस लेने के अलावा कांग्रेस के पास चारा क्या था? यह अलग बात है कि बाद में कांग्रेस ने उसी द्रमुक के साथ मिलकर संयुक्त मोर्चा का गठन किया और 10 वर्ष तक सरकार चलाई। किन्तु उस समय की परिस्थिति में इसे आप शत प्रतिशत ग़लत नहीं कह सकते। संसदीय प्रणाली में व्हिप की व्यवस्था हो गई है। आप पार्टी नेतृत्व के निर्णय से सहमत हों या नहीं, सदन में व्हिप के अनुसार ही मतदान करना है। अन्यथा आपकी सदस्यता जा सकती है। 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने संविधान में संशोधन कर दल-बदल के विरुद्ध प्रावधान किया और उसे दसवीं अनुसूचि के रूप में लाया गया। अगर कोई निर्वाचित होने के बाद दल बदलता है तो सदस्यता चली जाएगी।

कम से कम दो तिहाई सदस्यों के साथ दल बदलना पड़ेगा। इसलिए कहीं-कहीं थोक भाव में दल बदल हुए या किसी ने इस्तीफा देकर दल बदला, दोबारा चुनाव लड़ा या किसी सरकार को गिराया बचाया और उसकी सदस्यता पर फैसला होने में समय लग गया। यह तो नहीं कह सकते कि दल बदल कानून ने इस प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लगाया। बहुत सारे दल बदल देश में इस कानून के कारण ही नहीं हुए। इससे राजनीतिक अस्थिरता के अनेक खतरे टले हें। वास्तव में दल-बदल को पूरी तरह गलत बताने के लिए राजनीतिक दलों और उनके नेतृत्व के अंदर सुस्पष्ट वैचारिकता और उसके प्रति प्रतिबद्धता का माहौल चाहिए।

उस प्रतिबद्धता के साथ जो आए उसे टिकट मिले, जो नहीं हो उसे नहीं दिया जाए। जब तक ऐसा नहीं होता हमें दल-बदल को उसके गुण दोष के आधार पर देखना चाहिए।

रोज़गार

इवेंट मैनेजमेंट में भी है ब्राईट फ्यूचर

कोरोना काल में रोज़गार पर जो चोट पड़ी है, उससे उबरने में बहुत टाईम लग सकता है। एक अनुमान के अनुसार लगभग दो करोड़ नौकरियां कोरोना काल की भेंट चढ़ गई, लोग परेशान हैं रोज़गार के लिए ऊपर से बढ़ती महंगाई ने जीना दुभर कर दिया है। बहुत से लोग नौकरी छोड़कर अपनी कंपनी खोल अपना बिजनेस करने की ओर मुड़ गए हैं जो एक अच्छा मूव ही कहा जाएगा। रोज़गार के अनेक क्षेत्रों में एक है, इवमेंट मैनेजमेंट! इसमें छोटी बड़ी कंपनियों के सैकड़ों, इवेंट मैनेज किए जाते हैं। कारपोरेट, डीलर्स मीट, वेडिंग, फैशन शोज, प्रोडक्ट लांच, आर्टिस्ट एंड सेलिब्रेटी मैनजमेंट के अलावा कास्टिंग का काम भी भली प्रकार से किया। यह बहुत ही एक्साइटिंग फील्ड है जहां बहुत तरह की चीज़ें सीखने और करने को मिलती हैं। कुल मिलाकर इवेंट मैनेजमेंट कलात्मक और सृजनात्मक सोच से मेल खाता हुआ फील्ड है। इवेंट मैनेजमेंट मार्केटिंग और एडवरटाइजिंग का मिला जुला रूप है, जो उत्साह और रोमांच से भरपूर है। यह कमाल की फील्ड है इसमें विजुअलाइजेशन है, क्रिएटिव है, प्लानिंग हैं, वैन्यू मैनेजमेंट है और भरपूर एक्साइटमेंट है।

नेचर ऑफ वर्क

इवेंट मैनेजमेंट का काम अलग अलग तरह के कामों को सही समय और पूरी तरह सटीकता के साथ जोड़ना है, जो इस काम को क्लाइंट के मुताबिक दिए गए समय पर और दिए हुए बजट में बिना किसी परेशानी या दुर्घटना के निपटा देता है वही सबसे सफल इवेंट मैनेजमेंट है। समय का दबाव हमेशा रहता है, क्वालिटी को लेकर हमेशा किच किच रहती है और सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद कमी निकालने की गुंजाइश बची रहती है। इस काम का नेचर ही ऐसा है कि पसंद और नापसंद के बीच बड़ी बारीक रेखा होती है। इवेंट के आयोजन से पहले बजट को लेकर, वेन्यू को लेकर, मेन्यू को लेकर, सेलिब्रेटी को लेकर बड़ी आपाधापी मची रहती है। लेकिन यही आपाधापी इस काम का अनिवार्य हिस्सा है, जो काम पूरा होने पर सुकून और पैसा दोनों देती है।

स्किल्स/योग्यता

इवेंट मैनेजमेंट के काम में अलग अलग तरह के गुणों की जरूरत होती है और काम करते रहने से उनमें निरंतर सुधार भी होता रहता है। चाहे लीडरशिप क्वालिटी हो, या पीआर स्क्लि हो या मार्केटिंग स्क्लि हो, बजट बनाने का स्किल हो, रिस्क मैनेजमेंट स्किल हो, ये सारे स्किल्स इसमें काम आते हैं और उनमें निरंतर निखार भी आता रहता है।

हर व्यक्ति जो इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ना चाहता है को यह पता होना चाहिए कि उसमें कौन-कौन से स्किल्स हैं, जिनकी ज़रूरत इस काम में पड़ती है और जिनके बिना इस काम में आना गैर समझदारी का निर्णय हो सकता है।

कोर्स

इसके प्रमुख कोर्स है - डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट, एडवांस्ड डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट एंड पीआर, पीजी डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट एण्ड एक्टीवेशन जैसे पाठयक्रम हैं।

इन पाठयक्रमों के तहत आप क्लाइंट सर्विसिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, सेट डिजाइन, इवेंट प्लानिंग एंड कास्टिंग, इवेंट ब्रॉडिंग, प्रोडशन एवं तकनीक जैसे विषय पढ़कर इस फील्ड में महारत हासिल कर सकते हैं।

संभावनाएँ

एडिटवर्क्स स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन के विशेषज्ञों के अनुसार जितनी जल्दी आप इवेंट के काम को समझ जाएंगे उतनी जल्दी आप इसमें कामयाबी हासिल कर लें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है क्लाइंट को संतुष्ट करना। अगर आपने यह कर लिया तो वारे न्यारे।

वेतन

इस क्षेत्र में शुरुआत में भले ही आपको बतौर वेतन 10 से 15 हजार रुपए तक ही मिले लेकिन लगन, मेहनत और कौशल की बदौलत आपकी सैलरी लाखों में हो सकती है।

प्रमुख संस्थान

एडिटवर्क्स स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन

नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ इवेंट्स

कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, पुणे महाराष्ट्र

इस्लामी दुनिया

अफग़ानिस्तान : भारत ने भेजी 2500 टन गेहूं की खेप

तालिबान के सत्ता में आने के बाद खाद्यान्न की किल्लत से जूझ रहे अफग़ानिस्तान की मदद के लिए भारत ने 2500 टन गेहूं की पहली खेप पिछले दिनों रवाना की। यह गेहूं पाकिस्तान के रास्ते सड़क मार्ग से अफग़ानिस्तान जाएगा। मानवीय आधार पर भारत कुल 50 हजार टन गेहूं अफगानिस्तान भेजेगा। अमृतसर के अटारी वाघा बार्डर से विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, अफगान राजदूत फरीद मामुन्दजई और विश्व खाद्य कार्यक्रम के भारत में निदेशक बिश्व पाराजुली की मौजूदगी में गेहूं से भरे ट्रक रवाना किए।

शराब संग पकड़ा गया इमरान का सौतेला बेटा

लाहौर : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान का सौतेला बेटा पिछले दिनों देर रात लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम के पास शराब के साथ पकड़ा गया। पुलिस ने बताया कि इमरान के सौतेले बेटे मूसा मानेक के ख़िलाफ़ सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने का केस दर्ज किया गया है।

अरब शासकों, खुफिया प्रमुखों ने स्विस बैंक में छिपाए करोड़ों डॉलर

रियाद : मध्य पूर्व की बड़ी हस्तियों द्वारा एक स्विस बैंक में पैसा छिपाने का खुलासा हुआ है। स्विटजरलैंड के बैंक और जाने माने वित्तीय संस्था 'क्रेडिट सुइस' की एक रिपोर्ट में जिन खातों की जानकारियां लीक हुई है, वे अरब देशों के कई मौजूदा और पूर्व शासक व जासूस प्रमुखों से जुड़ी बताई जा रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, जार्डन के राजा-पानी ने गुप्त स्विस खातों में करोड़ों डॉलर जमा कि तो अरब क्रांति के दौरान मिस्र में सत्ता से बेदखल राष्ट्रपति होस्नी मुबारक के बेटों ने भी काफी पैसा छुपाया।

इस्राइली पीएम बेनेट की पहली आधिकारिक यात्रा

तेल अवीव : इस्राईल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेने अपनी पहली आधिकारिक यात्रा बहरीन की राजधानी मनामा पर गए। यह सब अब तक किसी भी तरह का इस्राईली पीएम का पहला बहरीन दौरा है। बेनेट ने बहरीन के विदेश मंत्री और उद्योग मंत्रियों से मुलाकात की। उनका बहरीन के क्रॉउन प्रिंस के साथ मिलने का भी कार्यक्रम प्रस्तावित रहा।

जासूसी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न

आलोक मेहता

एक बार फिर फोन से जासूसी पर हंगामा निश्चित रूप से निजता का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए सक्रिय रहना ज़रूरी है लेकिन पुराने अनुभवों के इस तथ्य को नहीं भुलाया जा सकता है कि विदेशी गुप्तचर एजेंसियां कुछ पत्रकारों, नेताओं, अधिकारियों, कुछ असली नक़ली संस्थाओं के पदाधिकारियों को जाने अनजाने भारत विरोधी गतिविधियों में उपयोग करते रहे हैं।

ऐसे गंभीर आरोप और कुछ प्रमाण मिलने पर इस्तीफे हुए, अदालती मामले चले, कभी सज़ा मिली या देश छोड़कर जाने की स्थिति तक बनी। इस संदर्भ में राजीव गांधी के सत्ताकाल में उछले एक गंभीर जासूसी कांड को याद किया जा सकता है। तब राम स्वरूप जासूसी काण्ड प्रकाश में आया था जिसमें एक विदेशी गुप्तचर एजेंसी द्वारा राजनीति और मीडिया से जुड़े लोगों के विरुद्ध भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा एकत्र सबके नामों का उल्लेख किए बिना मैंने एक ख़बर दिल्ली के प्रमुख दैनिक में 10 अक्तूबर 1985 को लिखी छपी। तब एक कानूनी नोटिस भी मिला। मैंने तो यह उल्लेख किया था कि इस कांड से राजीव गांधी सरकार के कुछ मंत्री संकट में आ सकते हैं

मेरे पास पर्याप्त तथ्य थे इसलिए कानूनी नोटिस का हमने कोई उत्तर नहीं दिया। जांच का काम आगे बढ़ने के बाद मामला अदालत तक पहुंचा और तीन माह बाद 28 जनवरी को कांग्रेस के चार मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। इनमें से एक दिल्ली के ही एक अन्य प्रमुख हिंदी दैनिक के पूर्व संपादक भी थे। इसलिए कम से कम यह तो माना जा सकता है कि नेता या पत्रकार जासूसी कांड में लिप्त मिल सकते हैं। हाल ही में अंग्रेजी प्रकाशनों में रक्षा - विदेशी मामलों के अनुभवी पत्रकार को चीन के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया है। यह बात तो सही है कि सरकारी एजेंसियां और देश विदेश की निजी एजेंसियां भी सालों से अधिकृत अथवा गैर कानूनी ढंग से भारत में जासूसी करती रही है। अब इजराइल की एक कंपनी के आधुनिक उपकरण से दुनिया के 14 देशों के साथ भारत के भी कई लोगों के फोन में सेंध लगाकर जासूसी का मामला विवाद में है।

पेगासस उपकरण की खरीदी और उसके उपयोग से जुड़ी तथ्यात्मक जानकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति पड़ताल कर रही है। न्यूयार्क टाइम्स ने तो दावा किया है कि भारत सरकार ने यह उपकरण खरीदा है जबकि सरकार इस विषय पर कोई स्पष्ट उत्तर देने के बजाय यही कह रही है कि उसने अनाधिकृत रूप से कोई जासूसी नहीं करवाई है। मतलब अधिकृत रूप से जासूसी के लिए सरकारी प्रक्रिया है। कम से कम अनुभवी नेताओं और पत्रकारों को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मुझे 32 साल पहले की घटना याद आती है। ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति थे, उनके करीबी वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल के साथ राष्ट्रपति भवन में बातचीत हो रही थी, पहले हम उनके स्टडी रूम में ही बात कर रहे थे, फिर राजनीतिक उठापटक पर बात शुरू होने पर ज्ञानी जी ने हमसे कहा चलो बाहर लॉन में बात करेंगे। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, ज्ञानी जी ने बाहर निकल कर खुद ही बताया कि तुम्हें मालूम नहीं है, आजकल दीवारों के मान भले ही न हो, टेलिफोन उठाए बिना कोई दूर बैठा हमारी बात सुन लेगा या रिकॉर्ड भी कर लेगा। उन दिनों ज्ञानी जी और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बीच मत भिन्नता और अविश्वास का दौर चल रहा था कि स्थिति यहां तक गंभीर थी कि कुछ नेता राष्ट्रपति को अपने अधिकार का उपयोग करके बर्खास्त करने तक की सलाह देने लगे थे, इस तरह फोन से टेपिंग, से बचाव के रास्ते निकाले जाते रहे।

रहस्य यह है कि किसके कहने पर इनके फोन में सेंध लगाई गई। जासूसी भी 2019 के चुनाव से कुछ पहले की तारीख़ों में हुई है। व्हाट्ऐप्प दावा करता रहा है कि उसके संदेश पूरी तरह सुरक्षित होते हैं। दुनियाभर में उसके 150 करोड़ उपभोक्ता हैं। इनमें से करीब 40 करोड़ भारत में हैं, इसलिए, व्हाटऐप्प की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और उसने बाकायदा अमेरिका की अदालत में इजरायल की कंपनी के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज कर दिया है। यह मामला आसानी से निपटने वाला नहीं है। इससे पहले भी परस्पर विरोधी संस्थानों और लोगों ने जासूसी के आरोपों पर बड़ी हाय तौबा मचाई लेकिन कभी किसी पर गंभीर कार्रवाई नहीं हो सकी। कांग्रेस गठबंधन की सरकार के दौरान एक प्रभावशाली मंत्री द्वारा अपनी ही सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री के कक्ष में जासूसी के उपकरण लगाने का आरोप सामने आया था। सरकार ने अपनी इज्ज़त बचाने के लिए इस मामले को दबा दिया। इसी तरह तत्कालीन थल सेना अध्यक्ष जनरल बी.के. सिंह (अब केन्द्रीय मंत्री) की जासूसी का गंभीर आरोप भी सामने आया था।

वर्तमान विवाद में असली मुद्दा यह है कि किसी एजेंसी ने इन चुनिंदा लोगों के फोन में ही सेंध क्यों लगाई? जो नाम सामने आए उनमें से कुछ पर नक्सल संगठनों, उनसे जुड़े संदिग्ध व्यक्तियों और देश विदेश में मानव अधिकारों के अथवा मानव अधिकार कार्यकर्ता के रूप में चर्चित रहे हैं।

रहस्य यह है कि किसके कहने पर इनके फोन में सेंध लगाई गई। जासूसी भी 2019 के चुनाव से कुछ पहले की तारीख़ों में हुई है। व्हाट्ऐप्प दावा करता रहा है कि उसके संदेश पूरी तरह सुरक्षित होते हैं। दुनियाभर में उसके 150 करोड़ उपभोक्ता हैं। इनमें से करीब 40 करोड़ भारत में हैं, इसलिए, व्हाटऐप्प की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और उसने बाकायदा अमेरिका की अदालत में इजरायल की कंपनी के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज कर दिया है। यह मामला आसानी से निपटने वाला नहीं है। मज़ेदार बात यह है कि इससे पहले भी परस्पर विरोधी संस्थानों और लोगों ने जासूसी के आरोपों पर बड़ी हाय तौबा मचाई लेकिन कभी किसी पर गंभीर कार्रवाई नहीं हो सकी। कांग्रेस गठबंधन की सरकार के दौरान एक प्रभावशाली मंत्री द्वारा अपनी ही सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री के कक्ष में जासूसी के उपकरण लगाने का आरोप सामने आया था। सरकार ने अपनी इज्ज़त बचाने के लिए इस मामले को दबा दिया। इसी तरह तत्कालीन थल सेना अध्यक्ष जनरल बी.के. सिंह (अब केन्द्रीय मंत्री) की जासूसी का गंभीर आरोप भी सामने आया था।

दूसरा मामला बड़ी कारपोरेट कंपनियों, नेताओं और नामी पत्रकारों कि महीनों तक फोन पर होती रही बातचीत की जासूसी के टेप सामने आने पर हंगामा मच गया था। लेकिन आज तक उस जासूसी के सूत्रधारों के नाम सामने नहीं आए और न ही किसी पर कोई कार्रवाई हुई। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, राजस्थान जैसे विभिन्न राज्यों में सत्ताधारियों द्वारा समय-समय पर अपने विरोधियों और अपने समर्थकों तक की जासूसी के आरोप सामने आते रहे हैं।

शायद यही कारण है कि इस बार भी जासूसी कांड को लेकर राजनीतिक हंगामा हो रहा है। इस विवाद से जुड़ा दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि नक्सली हिंसा अथवा आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े लोगों की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहायता करने वालों पर सरकारी या ग़ैर सरकारी स्तर पर नज़र रखने की पूरी संभावना रहती है। क़ानूनी रूप से अधिकार हो सकता है लेकिन देर सबेर यह ख़तरा बन सकता है कि देश के अंदर या बाहर से सहायता देने वाले लोगों से संपर्क होने पर वह भी संदेह के पात्र हो जाते हैं। नक्सली हिंसा में कांग्रेस के भी शीर्ष नेताओं की हत्या हुई है। अपने सत्ता काल में वह भी ऐसे लोगों पर नज़र रखती रही है।

भारत ही नहीं ब्रिटेन और अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों में भी सत्ताधारियों अथवा कारपोरेट कंपनियों द्वारा जासूसी के मामले सामने आते रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय रहने पर अन्य ख़तरों के साथ इस तरह के ख़तरों का भी सामना करना होता है। बहरहाल यह उचित समय है जबकि सरकार, सुप्रीम कोर्ट और संसद निजता के अधिकार की सीमाएं और किसी भी तरह की गुप्तचरी के नियमों को नए सिरे से तय करे। अभिव्यक्ति की आज़ादी तथा सुरक्षा व्यवस्था की लक्षमण रेखा निर्धारित होनी चाहिए।□□

आख़िर उत्तर प्रदेश प्रगति की राह कब पकड़ेगा?

पांच राज्यों में चुनावों के कई दौर गुज़र चुके हैं। जब ये पंक्तियां लिखी जा रही हैं, यूपी में 5वें दौर का चुनाव हो चुका है। पंजाब में भी चुनाव हो चुका है। न्यूज चैनल वाले अब एग्जिट पोल में लग गए। सबसे अधिक चर्चा उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों की विधान सभाओं के चुनावों की चर्चा ज़ोरों है। इन पांच राज्यों में यूं सभी राज्यों में ध्रुवीकरण का माहौल बनाने की पार्टियां पूरी कोशिश में हैं, परंतु इस ध्रुवीकरण की मार सबसे ज़्यादा अगर कोई राज्य झेल रहा है तो वह है उत्तर प्रदेश! संभवत: उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहां चुनावी माहौल में ध्रुवीकरण सबसे ज़्यादा होता है। ऐसे मुद्दे हवा में उछाले जा रहे थे, जिन्हें सिर्फ अनुचित कहा जा सकता है। ऐसा ही एक मुद्दा धार्मिक जातीय आधार पर समाज का ध्रुवीकरण है। इधर कोरोना का संकट गहरा रहा, उधर उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों की सरगर्मी तेज़ हो चुकी है।

जब से चुनावों की तारीख़ों के ऐलान हुआ था चुनाव प्रचार में तेज़ी तभी आ गई थी। ऐसा नहीं है कि इससे पहले चुनाव प्रचार का काम नहीं हो रहा था, सभी दल इस संदर्भ में पूरी कोशिश में लगे थे। यह आसानी से देखा जा सकता था कि उसके पास जितने साधन थे, वह उसी के अनुसार प्रचार कार्य में लगा था। इस प्रचार-कार्य पर उंगली तो उठाई जा सकती है, पर यह कहना सही नहीं होगा कि सब कुछ ग़लत हो रहा था लेकिन यह भी सही है कि जिन मुद्दों पर जोर दिया जाना चाहिए था वे कहीं हाशिये पर थे और ऐसे मुद्दे हवा में उछाले जा रहे थे, जिन्हें सिर्फ अनुचित कहा जा सकता है। ऐसा ही एक धार्मिक और जातीय आधार पर समाज का बंटवारा है। देश का प्रबुद्ध नागरिक पहले भी इस ध्रुवीकरण की इस प्रवृत्ति से चिंतित था, आज भी है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक बयान इसका ताज़ा उदाहरण है। उन्होंने एक चुनावी सभा में राज्य में चुनावी लड़ाई को अस्सी प्रतिशत बनाम बीस प्रतिशत के बीच मुक़ाबले का नाम दिया है हालांकि, उन्होंने यह कहकर अपने मंतव्य पर एक पर्दा डालने का प्रयास भी किया कि वह उनके विरोधी बीस प्रतिशत में वे लोग हैं जिनका रिश्ता आपराधिक गतिविधियों से है, पर यह बात समझने के लिए समझने के लिए किसी उच्च स्तरीय गणित की आवश्यकता नहीं है कि देश में और उत्तर प्रदेश में भी, धार्मिक आधार पर जनसंख्या का बंटवारा अस्सी प्रतिशत और बीस प्रतिशत ही है। मुख्यमंत्री योगी प्रतिशत की कुछ भी व्याख्या करें, पर देश की बीस प्रतिशत आबादी के प्रति उनका रुख किसी से छिपा नहीं है।

राजनेताओं को भले ही यह सौदा फायदे का लगता हो, पर उनका यह चुनावी गणित सारे देश की समरसता और एकता का संतुलन बिगाड़ने वाला है। ऐसा नहीं है कि चुनावों में धार्मिक भावनाओं को उभारने और उनका चुनावी लाभ उठाने का काम पहले नहीं होता था, पर पिछले कुछ सालों में यह खतरनाक प्रवृत्ति लगातार बढ़ी है। समूचि राजनीति को मात्र चुनावी लाभ की नज़र से देखने वाले हमारे राजनेताओं को उन मुद्दों की कोई चिंता नहीं है जिनका देश की जनता के हितों से सीधा रिश्ता है।

आज देश के सामने बेरोज़गारी एक गंभीर समस्या है। सरकार के सारे दावों के बावजूद देश में बेरोज़गारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसा ही दूसरा मुद्दा महंगाई है। आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले दो सालों में देश में मध्यम वर्ग का आकार सिकुड़ा है, अर्थात् मध्यम वर्ग वाले एक सीढ़ी नीचे उतर गए हैं। यह वही वर्ग है जो महंगाई की मार सबसे ज़्यादा झेल रहा है। आख़िर क्या कारण है कि महंगाई और बेरोज़गारी हमारे राजनेताओं को चिंतित नहीं करती? क्यों हमारे राजनेता मतदाताओं को कभी धार्मिक उन्माद की खुराक देते हैं और कभी संस्कृति के नाम पर राष्ट्रवाद की भावनाएं भड़काने की कोशिश करते हैं? मतदाताओं को हिन्दू मुसलमान में बांटना कोई ग़लत नहीं, एक अपराध है। गंभीर अपराध! खुलेआम अस्सी प्रतिशत बनाम बीस प्रतिशत की बात करके हमारे नेता यही अपराध कर रहे हैं। सवाल उठता है कि धर्म राजनीति का विषय बने ही क्यों? कोई किस विधि से पूजा-अर्चना करता है, यह उसका निजी निर्णय है। व्यक्ति की अपनी आस्था होती है, अपनी श्रद्धा होती है। इस आस्था श्रद्धा का राजनीतिकरण किसी के फायदे की चीज़ हो सकती है, पर इस प्रवृत्ति के चलते घाटे में हम ही रहते हैं, हम यानि भारत के लोग जिन्होंने अपने संविधान में सेक्युलर होने की शपथ ली है, जिन्होंने सोच समझकर देश के हर नागरिक को समानता का अधिकार दिया है। धर्म, जाति, वर्ण, वर्ग के नाम पर भारतीय समाज को बांटने की कोई भी कोशिश हमारे संविधान का उल्लंघन है, अपराध है और यह सब कुछ होते हुए देखते रहना भी एक अपराध से कम नहीं है। सह- अस्तित्व हमारे राष्ट्रीय चरित्र की गौरवशाली परंपरा और विशेषता है।

आज यदि कोई सबके विकास की बात करता है तो उसका सिर्फ यही अर्थ हो सकता है कि एक अरब तीस करोड़ भारतवासी साथ मिलकर विकास की राह पर आगे बढ़ें। चुनाव एक व्यवस्था है जो हमने अपने लिए स्वीकारी है, हम चुनाव के लिए नहीं बने इसलिए चुनाव में सफलता के लिए यदि हमें यानि भारतीयों को बांटने की कोशिश की जाती है तो इस कोशिश का हर संभव तरीक़े से विरोध होना चाहिए। प्रश्न अस्सी प्रतिशत बीस प्रतिशत का नहीं, पूरे सौ प्रतिशत का है राजनेताओं से निवेदन है कि देश के मतदाता को भारतीय ही बना रहने दें। उनको बांटकर अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए प्रयोग करना बन्द करें। इस महान देश की गौरवशाली परंपरा और उसूलों को बनाए रखने के लिए हर भारतीय को एक साथ मिलकर रहना होगा।

हम सब भारतीयों को निष्पक्ष होकर बिना किसी धार्मिक प्रवृत्ति से प्रभावित होकर मतदान करना होगा, तभी जाकर हमारी आने वाली पीढ़ियां महान भारतीय परंपरा सही सलामत सौंप पाएंगे, अन्यथा आने वाली पीढ़ियों की जो दुर्दशा होगी उसके हम ही ज़िम्मेदार होंगे। भारत देश महान है और यहां की जनता ''एकता में अनेकता'' भारत को और महान बनाती है, विभिन्न धर्म, समुदाय मिलजुल रहने से ही ये देश महान बनेगा। जब तक ये पंक्तियां आप तक पहुंचेगी, 2022 का चुनाव अपने अन्तिम मरहले में आ चुका होगा, और सभी पार्टियों को नतीजों का बेसबी से इंतज़ार होगा, नतीजा जो भी हो पर एक बात तो यह चुनाव में सही साबित कर ही गया कि उत्तर प्रदेश में आज भी जाति आधारित वोट का ही बोलबाला रहा है, कोई भी दल विकास के नाम पर भले ही वोट मांगे पर, विकास यूपी से कोसों दूर है। ये बात यूपी की जनता को पता नहीं कब समझ में आएगा कि विकास के लिए जाति नहीं योग्य पार्टी, योग्य उम्मीदवार और साम्प्रदायिकता के द्वेष को दूर करना होगा और हिन्दू/मुस्लिम के चक्कर में न पड़ कर सिर्फ विकास को ही प्राथमिकता देना होगा, तब कहीं जाकर उत्तर प्रदेश विकास की राह पर चलेगा। ❑❑

आज देश के सामने बेरोज़गारी एक गंभीर समस्या है। सरकार के सारे दावों के बावजूद देश में बेरोज़गारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसा ही दूसरा मुद्दा महंगाई है। आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले दो सालों में देश में मध्यम वर्ग का आकार सिकुड़ा है, अर्थात् मध्यम वर्ग वाले एक सीढ़ी नीचे उतर गए हैं। यह वही वर्ग है जो महंगाई की मार सबसे ज़्यादा झेल रहा है। आख़िर क्या कारण है कि महंगाई और बेरोज़गारी हमारे राजनेताओं को चिंतित नहीं करती? क्यों हमारे राजनेता मतदाताओं को कभी धार्मिक उन्माद की खुराक देते हैं और कभी संस्कृति के नाम पर राष्ट्रवाद की भावनाएं भड़काने की कोशिश करते हैं? मतदाताओं को हिन्दू मुसलमान में बांटना कोई ग़लत नहीं, एक अपराध है।

नंबर वन कार्लसन को हराया, 16 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने

एयरथिंग्स मास्टर्स ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैगनम कार्लसन को हराने के बाद भारतीय किशोर आर प्रगनानंदा का शानदार प्रदर्शन जारी है। उन्होंने 10वें और 12वें दौर में एलेक्जेंडर कोस्तानियुक को मात दी। 16 वर्षी खिलाड़ी ने दो जीत दर्ज की जबकि नोदरिबेक अब्दुसतोरोव से बाज़ी ड्रॉ खेली। हालांकि, रूसी ग्रेंडमास्टर इयान नेपोमनियाची से हार का सामना करना पड़ा। प्रगनानंदा दो जीत और एक ड्रॉ के बावजूद 15 अंकों के साथ 12वें स्थान पर बने हैं। अपने से अधिक रेटिंग के आंद्रे को 42 चाल में हराया। प्राग ने अपने दिन की शुरुआत अब्दुसतोरोव से बाज़ी ड्रॉ खेलकर की थी। नेपोमनियाची से हार झेलने के पूर्व महिला विश्व चैम्पियन कोस्तानियुक को 63 चाल में पराजित किया।

ख़ास ख़बरें

उत्तराखंड : खाई में गिरी बस 14 की मौत

चंपावत : सूखीढांग डांडा मीडार रोड पर पिछले दिनों एक भयंकर हादसा हुआ करीब 10:50 बजे बरातियों से भरी मैक्स 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में दूल्हे की दो बुआओं समेत 14 लोगों की मौत हो गई। मैक्स चालक और एक अन्य यात्री की हालत गंभीर बताई जारही है।

कनाडा : आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल कर प्रदर्शनों से निपटे

ओटावा : कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन त्रूदो ने कहा है कि उन्होंने कोविड-19 प्रतिबंधों के विरोध में ओटावा को पंगु बनाने वाले और सीमा पार यातायात को बाधित करने वाले ट्रक ड्राइवरों और अन्य लोगों के प्रदर्शन से निपटने के लिए आपातकालीन शक्तियों के इस्तेमाल पर त्रूदों को कनाडा में ट्रोल किया जा रहा है। हालांकि अमेरिका को जोड़ने वाले पुल से जाम खुलने लगा है। त्रूदो ने सेना के इस्तेमाल की संभावना से इंकार कर कहा कि आपातकालीन कदम निश्चित समय पर अमरिकी सीमा पर उठाए जाएंगे।

किसी भी समय हमले की आशंका : व्हाईट हाउस

अमेरिकी रक्षा मुख्यालय (पेंटागन) ने कहा है कि अमेरिका अब भी यह नहीं मानता कि रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन ने हमले का फैसला किया है, लेकिन संभव है कि रूसी सेना बिना किसी चेतावनी के आगे बढ़े। इस बीच व्हाईट हाउस ने किसी भी हमले की चेतावनी की आशंका जताते हुए कहा, हम अपनी खुफिया जानकारी पर कोई जानकारी नहीं देंगे, लेकिन क्षेत्र में जंग का तनाव है और अभी यह स्पष्ट नहीं है कि रूस कौन सा रास्ता चुनेगा, युद्ध का अथवा कूटनीतिक प्रयासों का।

आर्थिक राहत पैकेज के लिए भारत आएंगे श्रीलंकाई वित्तमंत्री

कोलंबो : श्रीलंका के वित्तमंत्री बेसिल राजपक्षे भारत से प्राप्त आर्थिक राहत पैकेज को औपचारिक रूप देने के लिए अगले कुछ दिनों के दौरान भारत का दौरा करेंगे। गंभीर विदेशी मुद्रा संकट का सामना कर रहे द्विपीय देश के लिए भारत ने जनवरी में खाद्य के आयात को लेकर 90 करोड़ डॉलर के ऋण की घोषणा की थी। पीएरिस ने कहा कि दिसंबर में राजपक्षे की भारत यात्रा उपयोगी साबित हुई।

सलाम को आम कीजिए 1

इस्लाम एक भरपूर जीवन बिताने की व्यवस्था है जिसमें इंसानों की कामयाबी व कामरानी उनके ज़िन्दगी गुज़ारने का तरीक़ा और समाजी हालात के संबंध से उनकी भरपूर रहनुमाई की गयी है, इस्लाम जहां इंसानों को व्यक्तिगत ज़िन्दगी के रहनुमा उसूलों और हिदायात से अवगत कराता है वहीं सामूहिक ज़िन्दगी में भी उसकी भरपूर रहनुमाई मौजूद है। सब के साथ अच्छा बर्ताव, नर्मी के साथ पेश आना, दूसरों की सेवा, बड़ों का एहतराम, उनके साथ अख़लाक़ से पेश आना, छोटों पर प्रेमभाव, घमंड को अपने पास न आने देना, जहां तक हो सके अपने घर वालों की ज़रूरतों को पूरा करना, पड़ोसियों के अधिकार, सलाम में आगे-आगे रहना और तमाम अल्लाह के बंदों और उसकी मख़लूक के अधिकारों की अदायगी की इस्लामी तालीमात न केवल मोमिनों के लिए रोशन हिदायात है बल्कि दूसरों और इस्लाम के इंकार करने वाले भी उनको अपनाकर अमन और सुकून से भरपूर समाज और मुआशरा बना रहे हैं। इस हक़ीक़त से भी इंकार मुमकिन नहीं है कि सरवरे क़ायनात हज़रत मुहम्मद सल्लल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम आख़िरी नबी हैं और आप सल्ल॰ की रिसालत आलमी रिसालत है फिर जिस तरह आप आख़िरीनबी और आलमी रसूल हैं उसी तरह आपकी तालीमात आपकी हिदायात भी आख़िरी आलमी हैसियत की हामिल हैं। अब क़यामत तक शरीअते मुहम्मदिया पर अमल ही निजात का ज़रिया और मौत के बाद की सफलता का जामिन है। यह भी एक रौशन हक़ीक़त है कि आक़ा रसूल सल्ल॰ ने इस्लामी इंक़लाब लाकर अपनी 23 वर्षीय संघर्ष के ज़रिए एक ऐसे समाज को वजूद बख़्शा जो क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए न केवल हिदायत की वजह है बल्कि वह अन्य क़ौम व मिल्लत के लिए भी रास्ता दिखाने वाला है। हमारे समय की बहुत सी क़ौमें बिना ऐलान किए उनमें कुछ बातों पर अमल करके कामयाब भी हो रही हैं, इसलिए हमें भी अपने समाज की इस्लाह और बुराईयों पर क़ाबू पाने के लिए उसी तरीक़े पर अमल करना होगा जिस पर चलकर हज़रते सहाबा कराम और उनके बाद के लोगों ताबायिन, तबआ ताबिईन, फोकहा, मुहद्दीसीन, मुफस्सीरीन, मशाइख़ और सूफियाए कराम ने समाज को भलाई और कल्याण की राह दिखाई।

आज हम अपने समाज और उसमें आई बुराईयों का अगर जाएज़ा लें तो इसमें सबसे बड़ी वजह आप घमंड और बड़ाई को पाएंगे, यह दोनों कमियां ही हमारे समाज की सैकड़ों बुराईयों और बिगाड़ की जड़ हैं। इंसान में अहंकार और घमंड की बीमारी जन्म ले लेती है, तो गुनाहों को अपने लिए ज्ञान समझने लगता है, दूसरों के अधिकार को अपनी शान समझने लगता है, दूसरों के अधिकार को पामाल करना वह अपना हक़ समझने लगता है और हद की बात यह होती है कि अपने ख़ालिक और मालिक तक के हक़ूक़ और फरायज़ से जानबूझ कर या नादानी और नासमझी में रूगरदानी करना

दूसरों को छोटा साबित करने के लिए दौलत का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ बड़प्पन की बीमारी का नतीजा होते हैं, सरकारे दो आलम सल्ल॰ इन तमाम बीमारियों के लिए जो नुस्खा दिया और अपनी निगरानी में काम में लाकर उम्मत की जो रहनुमाई की है वह इस उम्मत की एक ऐसी शान है जो उसे दूसरी क़ौमों से अलग करता है। आपने अलग-अलग मौक़ों पर समाजी इस्लाह के लिए सलाम में पहल का एहतमाम के साथ इरशाद फरमाया है।

अपनी ज़िन्दगी का खेल बनाने तक से परहेज़ नहीं करता। घमंड के ज़रिए अपनी मेहनत की कमाई लुटाना जायज़-नाजायज़ तरीक़े पर पहले ख़र्चे और दूसरों को छोटा साबित करने के लिए दौलत का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ बड़प्पन की बीमारी का नतीजा होते हैं, सरकारे दो आलम सल्ल॰ इन तमाम बीमारियों के लिए जो नुस्खा दिया और अपनी निगरानी में काम में लाकर उम्मत की जो रहनुमाई की है वह इस उम्मत की एक ऐसी शान है जो उसे दूसरी क़ौमों से अलग करता है। आप सल्ल॰ ने अलग-अलग मौक़ों पर और अहादीस में समाजी इस्लाह के लिए तवाजोह व इंकेसारी, हुस्ने अख़लाक़ और सलाम में पहल के एहतमाम के साथ इरशाद फरमाया है।

तवाज़ो व इंकसारी और अच्छे अख़लाक़ इंसानी ज़िन्दगी के वह जौहर है जो दूसरों को तो फायदा पहुंचाते ही हैं, खुद उन जवाहर को इस्तेमाल करने वाला भी अपनी ज़ात में इन अच्छी खूबियों के ज़रिए आनंद और ताज़गी महसूस करता है, सरकारें दो आलम सल्ल॰ का इरशाद है कि:-

''कोई सदक़ा माल को कम नहीं करता है और जो जितना अधिक दरगुज़र करता है अल्लाह उसकी इज्ज़त उतनी ही बढ़ाते हैं और जिसने अल्लाह के लिए तवाज़ोअ की अल्लाह ने उसे ऊंचा किया।'' (मुस्लिम शरीफ़)

मुस्लिम शरीफ की ही एक दूसरी रिवायत में आप सल्ल॰ का इरशाद है कि :-

''अल्लाह तआला ने मेरी ओर वह्यी फरमाई कि तुम तवाज़ोअ अख़्तियार करो यहां तक कि तुम में से कोई दूसरे पर फख़्र न करे और न दूसरे पर ज़्यादती''

आप सल्ल॰ ने इरशाद फरमाया कि :-

''अल्लाह तआला ने जिस पैग़म्बर को भी दुनिया में भेजा उसने बकरियां चराईं, सहाबा ने अर्ज़ किया और आपने भी, आप सल्ल॰ ने फरमाया ''हाँ'' मैं चंद कीरात पर मक्का वालों की बकरियां चराता था।'' (बुख़ारी शरीफ़)

हुस्ने अख़लाक़ के तअल्लुक़ से स्वयं अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आख़री नबी हज़रत मुहम्मद सल्ल॰ के ओसाफ बयान करते हुए इरशाद फरमाया ''बेशक आप सल्ल॰ आला अख़लाक के मालिक है (सूरह नून)

हज़रत अनस रज़ि॰ की जो लगातार दस वर्ष तक आप की ख़िदमत में रहे शहिद है कि,

''रसूलुल्लाह सल्ल॰ अख़लाक़ के लिहाज़ से लोगों में सबसे आला अख़लाक के मालिक थे'' आप सल्ल॰ ने अख़लाक़े हसना की हिदायात और तरग़ीब देते हुए इरशाद फरमाया कि

''मोमिन के नाम-ए-आमाल में क़यामत के दिन हुसने अख़लाक़ से बढ़कर कोई चीज़ भारी नहीं होगी। (तिर्मिजी)

एक अवसर पर सहाबा कराम ने आप सल्ल॰ से अर्ज़ किया कि लोगों को जन्नत में पहुंचाने वाले आमाल क्या है? आपने फरमाया, ''अल्लाह का खौफ़ और अख़लाक़े हसना।'' (तिर्मिजी) (जारी)

नूरे क़ुरआन

सूरा फातिहा नं॰ 01

अनुवाद और व्याख्या : शैख़ुल हिन्द र.अ.

यह सूरा मदीने में उतरी इसमें सात आयतें हैं।

प्रारंभ करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो असीम कृपालु महादयालु है।

'रहमान' और 'रहीम' दोनों अतिश्योक्ति के शब्द हैं। रहमान में रहीम से अधिक अतिश्योक्ति हैं इन बातों का अनुवाद मैं ध्यान में रखा गया है।

सब प्रशंसायें अल्लाह के लिए हैं।

अर्थात् तमाम उत्तम से उत्तम प्रशंसायें जो सदैव सदैव के लिए हो चुकी हैं और जो होंगी अल्लाह ही के योग्य हैं क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु और उपहार का पैदा करने वाला और देने वाला है। माध्यम से दे या बिना माध्यम के, जैसे धूप के कारण यदि किसी को गर्मी या प्रकाश पहुंचता है तो वह वास्तव में सूर्य ही की देन है।

जो सारे जहानों का पालनहार है।

जगत् के समूह को आलम कहते हैं इसीलिए उसका बहुवचन नहीं लाते मगर आयत में आलम में तात्पर्य जगत् की प्रत्येक जाति से है इसलिए बहुवचन लाये हैं। जैसे 'जिनों' की दुनिया, 'फरिश्तों' की दुनिया, 'इंसानों' की दुनिया। ताकि प्रत्येक जाति का अल्लाह का पैदा किया हुआ होना भली भांति सिद्ध हो जाये।

जो असीम कृपालु महादयालु है, जो बदले के दिन का मालिक है।

विशेष रूप से बदले के दिन का मालिक कहने का प्रथम कारण यह है कि उस दिन बड़े-बड़े मामले सामने आयेंगे। ऐसा भयानक दिन न पहले हुआ और न आगे होगा। दूसरे उस दिन अल्लाह के अतिरिक्त किसी को प्रत्यक्ष हुकूमत भी प्राप्त न होगी।

हम आप ही की उपासना करते हैं और हम आप ही से सहायता चाहते हैं।

इस आयत से ज्ञात हुआ कि अल्लाह के अतिरिक्त किसी से वास्तव में सहायता चाहना बिल्कुल उचित नहीं, हां यदि किसी अल्लाह के प्रिय बन्दे को केवल अल्लाह की कृपा के लिए मध्यस्थ मानकर प्रत्यक्ष रूप में सहायता मांगे यह उचित है क्योंकि यह सहायता वास्तव में अल्लाह ही से सहायता मांगना है।

हम को सीधा रास्ता बता दीजिए। उन लोगों का रास्ता जिन पर आप ने कृपा की है।

जिन पर अल्लाह की कृपा हुई वे चार वर्ग हैं : 1. रसूल, 2. सिद्दीक़ लोग, 3. शहीद, 4 और अल्लाह के नेक बन्दे। क़ुरआन शरीफ की सूरा नं॰ 4 रुकू नं॰ 8 के अंत में इसका स्पष्ट वर्णन किया गया है।

रुकू नं॰ 1

जिन पर आप का क्रोध हुआ और वे रास्ते से भटके।

क्रोध होने वालों से यहूदियों की ओर और पथ भ्रष्ट होने वालों से इसाईयों की ओर संकेत है। दूसरी आयतें और हदीसें इस की साक्षी है और सीधे मार्ग से वंचित और पथभ्रष्ट होना दो प्रकार से होता है। 1. अज्ञानता, 2. जानबूझकर कोई पथभ्रष्ट वर्ग अगला हो या पिछला। इन दो कारणों के अतिरिक्त किसी तीसरे कारण से नहीं होता। सो इसाई तो प्रथम कारण से और यहूदी दूसरे कारण से पथभ्रष्ट हुए हैं।

यह सूरा अल्लाह ने बन्दों की ज़बान से कही कि जब हमारे दरबार में उपस्थित हों तो हम से इस प्रकार प्रार्थना किया करो। सूरा के अन्त में आमीन कहना अच्छा है। यह शब्द क़ुरआन से अलग है और इस शब्द का अर्थ यह है कि ऐ अल्लाह ''ऐसा ही हो'' नेक बन्दों का अनुकरण और अवज्ञाकारियों से दूरी प्राप्त हो। इस सूरा के पूर्वार्द्ध में अल्लाह की प्रशंसा उत्तरार्द्ध में बन्दे के लिए प्रार्थना है।

(सूरा बक़रा नं॰ 02)

यह सूरा मदीने में उतरी इसमें 286 आयतें 40 रुकू हैं।

प्रारंभ करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो असीम कृपालु महादयालु है।

अलिफ़ लाम्मीम।

अलिफ़ लाम्मीम इन शब्दों को मुकत्तआत कहते हैं इनके वास्तविक अर्थों तक किसी की पहुंच नहीं केवल अल्लाह और उसके रसूल को उनके अर्थ का पता है। इसके अर्थ में गुप्त रहस्य है जो किसी विशेष कारण से गुप्त रखे गये हैं और कुछ विद्वानों ने जो इसके अर्थ के लिए उससे केवल उदाहरण उद्देश्य है, यह नहीं कि अल्लाह ने उसका यही मतलब लिया है।

मोदी सरकार के लिए राष्ट्रपति चुनाव होगा

अगली चुनौती

आर॰ राजगोपालन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किसी संकट को अवसर में बदलने में यकीन करते हैं। अगले कई सप्ताहों के दौरान उन्हें कुछ कड़ी राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना है। यदि वह उन पर क़ाबू पाने में सफल हो जाते हैं, तो यह 2024 के संसदीय चुनावों में उनकी सुचारू वापसी की नींव रख सकता है। वैसे इस वर्ष बजट के रूप में उन्होंने अभी अभी एक बाधा पार कर ली है, जिसे वित्तमंत्री ने 'अमृत काल' का बजट कहा है। मोदी के सामने आगामी चुनौती है, उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव। चूंकि चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार पर लगे तमाम प्रतिबंधों में कुछ ढील दी है, ऐसे में मोदी पांच राज्यों के चुनिंदा जिला मुख्यालयों में जाना चाहेंगे। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे 10 मार्च को आएंगे और तब मोदी की वास्तविक राजनीतिक चुनौती शुरू होगी और वह है अगले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव है। यह देखना होगा कि नरेन्द्र मोदी अपनी पसंद का चुनाव कैसे करेंगे और उनके पास विकल्प क्या है?

पहले बजट पर लौटते हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रभावी ढंग से भाजपा के 2019 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल भाजपा के तकरीबन सभी प्रमुख मुद्दों को अमल में लाया है। दिलचस्प यह है कि मोदी, दिवंगत अरुण जेटली और निर्मला सीतारमण, इन तीनों ने घोषणा पत्र के मसौदे को मंज़ूरी दी थी। बजट में बड़े आर्थिक सुधारों को शामिल किया गया। क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल मुद्रा का ज़िक्र भाजपा के घोषणा पत्र में नहीं था, उसे भी भारतीय अर्थ व्यवस्था में जगह दी गई है। मोदी प्रशासन के लिए क्रिप्टो करेंसी एक बड़ी चुनौती हैं। भाजपा ने इस संकट की भी पार कर लिया है। इसकी ज़िम्मेदारी अब रिज़र्व बैंक पर डाल दी गई है।

संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस चल रही है। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने काफी उत्तेजक भाषण दिया है, मगर वह भाजपा की चाल में उलझ गए। न तो कांग्रेस और न ही तृणमूल ने कार्यवाही को बाधित किया हैं और इससे मोदी सरकार को पर्याप्त राहत है और अपनी रणनीति पर काम करने का मौक़ा मिला है।

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव को अनेक पर्यवेक्षक मोदी सरकार की दूसरी पारी की मध्यावधि समीक्षा की तरह देख रहे हैं। औसतन हर

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 अप्रैल को और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म होगा। मोदी को इन शीर्ष पदों के उम्मीदवारों के चयन को लेकर काफी मशक्कत करनी होगी। राष्ट्रपति के पिछले चुनाव के समय 2017 में भाजपा के पास भारी बहुमत था, क्योंकि तब शिवसेना और अकाली दल एनडीए का हिस्सा थे।

तीसरे माह में देश के किसी भी कोने में होने वाले चुनाव अपने आप में चुनौती हैं और इन सब में जीतने की इच्छा ने मोदी पर अतिरिक्त दबाव बनाया है। वह अपनी पार्टी के वोट दिलाने वाले सर्वोच्च नेता है और हर चुनाव में अपनी पार्टी का नेतृत्व वही करते हैं। मोदी ने पांच राज्यों में चुनाव प्रचार का एक दौर पूरा कर लिया है। पार्टी के अंदरूनी लोग कहते हैं कि वर्चुअल प्लेटफार्म में भी नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति हज़ारों लोगों की उपस्थिति में होने वाली सभाओं जैसी प्रभावी होती है। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश और मणिपुर के चुनाव में विजय हासिल करने में भाजपा को मुश्किलें नहीं आनी चाहिए। लेकिन पंजाब और गोवा में उसे धक्का लग सकता है और इससे मोदी को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 अप्रैल को और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म होगा। मोदी को इन शीर्ष सांविधानिक पदों के उम्मीदवारों के चयन को लेकर काफी मशक्कत करनी होगी। राष्ट्रपति के पिछले चुनाव के समय 2017 में भाजपा के पास भारी बहुमत था, क्योंकि तब शिवसेना और अकाली दल एनडीए का हिस्सा थे। यही नहीं, तब तमिलनाडू में अन्नाद्रमुक दो तिहाई बहुमत के साथ सत्ता में थी और उसने रामनाथ कोविंद का समर्थन किया था। लेकिन अब परिदृश्य बदल गया है। तमिलनाडू में द्रमुक सरकार में है और 2019 में दो केन्द्र शासित क्षेत्रों में बदले जाने के बाद से जम्मू कश्मीर की विधानसभा बहाल नहीं हुई है। इसके अलावा बहुत कुछ पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों पर भी निर्भर करेगा। इसलिए मोदी को राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार की जीत के लिए आवश्यक मत प्राप्त करने के लिए भारी संकट का सामना करना पड़ सकता है।

इसलिए मोदी को राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार की जीत के लिए आवश्यक मत प्राप्त करने के लिए भारी संकट का सामना करना पड़ सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों तथा सारी विधानसभाओं के सदस्यों को मिलाकर इलेक्टोरल

बाक़ी पेज 11 पर

कैंसर की चुनौती से जूझ रहा भारत

देवेन्द्रराज सुथार

प्रतिवर्ष 04 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस भयानक बीमारी की चपेट में हर वर्ष सबसे अधिक लोग आते हैं और समय पर इलाज नहीं हो पाने के कारण असमय ही काल कवलित हो जाते हैं। कैंसर एक ऐसा रोग है जो किसी भी आयु में हो सकता है। यह एक साल के बच्चे से लेकर 80 वर्ष के बुज़ुर्ग तक में पाया जा सकता है। कैंसर के सौ से अधिक प्रकार हैं।

आमतौर पर शरीर का वज़न बढ़ाने व शारीरिक सक्रियता में कमी आने तथा दोषपूर्ण व असंतुलित खान-पान, व्यायाम नहीं करने, नशीले पदार्थों के रूप में अल्कोहल की अधिक मात्रा का सेवन करने से इस रोग के शिकार होने की आशंका अधिक रहती है। चाय और कॉफी जैसे पेय पदार्थों के आदी व्यक्ति को भी कैंसर होने का ज़्यादा ख़तरा रहता है क्योंकि चाय और कॉफी में चार हजार से अधिक घातक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति में कैंसर होने की अधिक आंशका होती है। कैंसर एक अनुवांशिक बीमारी होने के कारण कई बार पीड़ित माता-पिता के जीन के माध्यम से उनकी संतान में भी आ जाती है। वहीं दवाओं के साइड इफेक्ड्स से भी कैंसर होने की बात की जाती है।

नेशनल हैल्थ प्रोफाइल-2019 की रिपोर्ट के मुताबिक एन.सी.डी. क्लीनिक ने 2017 से 2018 के बीच कैंसर के मामलों की पहचान की है। आंकड़ों पर ग़ौर करें तो इस वर्ष के अंतराल में देश में कैंसर के मामले 324 प्रतिशत यानि 03 गुणा से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। राजस्थान में 2017 में सरकारी एन.सी.डी. केन्द्रों में पहुंचे 30,91,378 लोगों में से 1358 लोगों को सामान्य कैंसद निकला। वहीं 2018 के दौरान यह आंकड़ा बढ़कर 3414 हो गया। यह करीब 150 प्रतिशत यानि डेढ़ गुना बढ़ोत्तरी है। 2017 में 3,57,23,660 लोग जांच कराने पहुंचे। इनमें से 39,635 लोगों में सामान्य कैंसर पाया गया। 2018 में यह संख्या बढ़कर 6,51,94,599 हुई। इनमें 1,68,122 में सामान्य कैंसर की पुष्टि हुई।

गुजरात में 2017 में 3939 कैंसर पीड़ितों की पुष्टि हुई थी। 2018 में यह संख्या बढ़कर 72,169 हो गई। यानि गुजरात में सामान्य कैंसर के नए मामले 68,230 बढ़े हैं। गुजरात के बाद सबसे ख़राब हाल कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल का रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि लोगों की बदलते लाइफस्टाइल तनाव, खान-पान की आदतें, शराब और तंबाकू सेवन इसकी बड़ी वजह रही है।

हर दिन औसतन 1300 से अधिक लोग इस डरावनी बीमारी के शिकार हो रहे हैं। हर वर्ष कैंसर के 10 लाख नए मामलों का निदान किया जा रहा है और 2035 तक हर वर्ष कैंसर के कारण मरने वालों की संख्या 12 लाख तक बढ़ने की आशंका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के बाकी देशों के मुक़ाबले भारत में कैंसर रोग से प्रभावितों की दर कम होने के बावजूद यहां 15 प्रतिशत लोग कैंसर के शिकार होकर अपनी जान गंवा देते हैं।

डब्ल्यू.एच.ओ. के मुताबिक 172 देशों की सूचि में भारत का स्थान 155वां है। वर्तमान में कुल 24 लाख लोग इस बीमारी के शिकार हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 42 प्रतिशत पुरुष और 18 प्रतिशत महिलाएं तंबाकू के सेवन के कारण कैंसर का शिकार होकर अपनी जान गंवा चुके हैं। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के एक प्रतिवेदन के अनुसार देश में हर वर्ष इस बीमारी से 70,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है।

कैंसर संस्थान की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर वर्ष सामने आ रहे साढ़े 12 लाख नए रोगियों में से लगभग 7 लाख महिलाएं होती हैं। लगभग इनमें से आधी, साढ़े 3 लाख महिलाओं की मौत हो जाती हे। इनमें से भी 90 प्रतिशत की मृत्यु का कारण रोग को गंभीरता से नहीं लेना है। ये महिलाएं डॉक्टर के पास तभी जाती हैं जब बीमारी अनियंत्रित स्थिति में पहुंच जाती है। ऐसी स्थिति में यह बीमारी लगभग लाइलाज हो चुकी होती है।

नि:संदेह, यदि किसी व्यक्ति को कैंसर से बचाव करना है या कोई देश अपने को कैंसर मुक्त राष्ट्र बनाने सपना देखता है तो उसे अपने देश में धड़ल्ले से बिक रहे मादक व नशीले पदार्थों व शराब की फैक्ट्रियों पर राजस्व की चिंता किए बग़ैर रोक लगाने के लिए क़दम उठाने होंगे। यहां तक कि मोटापा बढ़ाने का कारण बन रहे जंक फूड पर फैट टैक्स लागू करके इसके सेवन से आमजन को बचाने के लिए प्रयत्न करने होंगे।

कैंसर को लेकर जो प्रमुख बात निकल कर सामने आ रही है वह है लोगों का इस रोग के प्रति लापरवाह रवैया। इससे पता लगता है कि समाज में एड्स की तरह कैंसर के रोगियों के प्रति भी भेदभाव बरकरार है, इसी वजह से लोग तुरंत इस रोग के बारे में जानकारी, देने से संकोच करते हैं। हमें इस रोग से जुड़े मिथकों व विकृत मानसिकता को दूर करने के लिए जन जागृति कार्यक्रमों में तेज़ी लानी होगी।

लक्ष्मण से मिला सफलता का गुरुमंत्र

यश ढुल

अंडर-19 विश्व कप का ख़िताब और रणजी ट्रॉफी के अपने पहले ही मैच की दोनों पारियों में शतक लगाकर यश ढुल ने 19 वर्ष की आयु में मानसिक मज़बूती का बखूबी परिचय दिया है। उनके इस प्रदर्शन के पीछे वीवीएस लक्ष्मण, रोहित शर्मा, विराट कोहली के दिए गुर साझा किए गए अनुभव छुपे हैं। यश ने पिछले एक दैनिक समाचार पत्र से कहा कि विश्व कप के दौरान लक्ष्मण ने उन्हें मानसिक रूप से मज़बूत होना सिखाया तो रोहित और विराट ने अपने अनुभवों को साझा कर बताया कि उन्हें कैरियर को किस तरह से आगे बढ़ाना है। यही कारण है कि अंडर-19 विश्व विजेता टीम के कप्तान यश अपने वरिष्ठ क्रिकेटरों से बात करने का कोई मौक़ा नहीं छोड़ते हैं।

यश के अनुसार एनसीए प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण और कोच ऋषिकेश कानितकर से विश्व कप के दौरान काफी सीखने को मिला। लक्ष्मणा ने उन्हें बताया कि मैच के लिए किस तरह मानसिक रूप से तैयार करना है। वह चीज़ करो जो अच्छा करने के लिए प्रेरित करती हो। किसी को गाना सुनना पसंद है तो वह वह करे। कोई पूरी तरह फोकस रहना चाहता है तो वह ऐसा करे, बस दबाव न लें। विराट और रोहित ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि किस तरह से आगे बढ़ना है।

यह पूर्व कप्तान विराट कोहली को आदर्श मानते हैं। वह उन्हीं की तरह मेहनत कर सफलता की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं। बीते 21 साल की मेहनत के कारण ही उन्हें शुरुआती सफलता मिल रही है।

वह कहते हैं कि उन्हें हमेशा अपनी मेहनत पर विश्वास रहा। सोच थी कि जब भी मौक़ा मिलेगा तो अपना सौ प्रतिशत दूंगा। उन्होंने छोटे छोटे गोल निर्धारित किए हैं रणजी ट्रॉफी पर पूरा ध्यान दिया उसके बाद आईपीएल पर फोकस करेंगे।

दिल्ली के चयनकर्ता चैतन्य नंदा और आशु दानी ने रणजी में उनकी सीधे अन्तिम एकादश में लेने की सिफारिश की थी।

ओलंपिक 2028 : कई खेलों पर मंडरा है ओलंपिक से बाहर होने का संकट

भविष्य में शायद ऐसा मुमकिन हो की अनेक खेल जो आज खेले जा रहे हैं ओलंपिक्स प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के लिए लिटिंग ही न हो। मुक्केबाज़ी, भारोत्तोलन और मॉडर्न पेंटार्थलान को लास एंजिल्स में 2028 में होने वाले ओलम्पिक खेलों में अपना स्थान बरकरार रखने के लिए 18 माह के अंदर अपनी व्यवस्था में सुधार करने के लिए कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक सतिमि (आईओसी) के अध्यक्ष थॉमस बाक ने मुक्केबाज़ी और भारोत्तोलन के शासी निकायों के बारे में कहा कि वे हमेशा समस्याएं पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि इन खेलों में नेतृत्व से जुड़े मसलों और भ्रष्टाचार और डोपिंग के मुद्दों पर चिंता व्यक्त की। मॉडर्न पेंटाथलान को आइओसी ने अपनी स्पर्धाओं से घुड़सवारी को हटाने के लिए कहा है जिस पर खिलाड़ियों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

इन तीनों खेल को ओलंपिक 2028 के कार्यक्रम की शुरूआती सूचि में शामिल नहीं किया गया है। इस कार्यक्रम को मंज़ूरी के लिए फरवरी में आईओसी सदस्यों के सामने रखा जाएगा। सूचि में स्क्वेटबोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिग शामिल हैं। ये तीनों खेल पहली बार तोक्यो ओलंपिक में शामिल किए गए थे। इससे वे भविष्य में ओलंपिक प्रसारण कार्यक्रम से होने वाली आय हासिल करने के हक़दार भी बन जाएंगे जो प्रति खेल कम से कम एक करोड़ 50 लाख डॉलर है। जिन तीन खेलों को हटाया गया है उनके पास अब भी सूचि में शामिल होने का मौक़ा रहेगा। बाक ने कहा कि उन्हें आईसीसी कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों को अपने खेल के शासन और संगठनात्मक संस्कृति में बदलावों से संतुष्ट करना होगा।

नंबर वन जोकोविच की वर्ष 2022 की पहली जीत

दुनिया के नंबर एक सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने दुबई चैम्पियनशिप में इटली के लोरेंजो मुसेटो को सीधे सेटों में 6-3, 6-3 से हराकर इस वर्ष की अपनी पहली जीत दर्ज की। जोकोविच पिछले दिनों टीकाकरण न कराने के कारण आस्ट्रेलियन ओपन में अपने ख़िताब की रक्षा के लिए नहीं उतर सके थे। मेलबर्न पहुंचने के बाद उनका वीज़ा रद्द कर दिया था। संयुक्त अरब अमीरात ने इस टूर्नामेंट के लिए उन्हें अनुमति प्रदान की और नोवाक ने उस टूर्नामेंट में जीत से शुरुआत की। जिसे वह पांच बार जीत चुके हैं। 74 मिनट चले मुक़ाबले में जोकोविच ने पांच एसेज सहित 14 विनर्स लगाए। मुसेटी ने पिछले वर्ष फ्रेंच ओपन में उनके ख़िलाफ दो सेट जीते थे लेकिन दुबई में जोकोविच ने प्रतिद्वंदी को मौक़ा नहीं दिया।

जीत के बाद जोकोवच ने कहा, 'कुछ अवसर थे जब मैं अच्छा खेला तो कुछ बेजा ग़लतियां भी कीं लेकिन जब आप लंबे समय बाद मैच खेल रहे हों तो ऐसा हो सकता है। हालांकि जोकोविच की नंबर वन क कुर्सी पर खतरा मंडरा रहे हैं। उन्हें अपनी शीर्ष रैंकिंग बचाने के लिए रूस के दानिल मेदवेदेव से कड़ी चुनौती मिल रही है। मेदवेदेव यदि मैक्सिको में होने वाले टूर्नामेंट में ख़िताब जीतने में सफल रहे (28 फरवरी) को वह जोकोविच को नंबर एक कुर्सी से हटा देंगे। यदि मेदवेदेव ऐसा करने में सफल रहे तो येवेगनी कैफिलनिकोव (1999) और मरात साफिन (2000-01) के बाद ऐसा करने वाले तीसरे रूसी होंगे।

पेट दर्द के अनेक कारण हो सकते है

पेट दर्द सबको समय-समय पर हो जाता है। लक्षणों के आधार पर डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता हो सकती है। आईये जाने क्या-क्या समस्या हो सकती है जिनसे पेट दर्द होता है।

गैस्ट्रिटिस

भोजन को पचाने में मदद करने वाले तरल में बहुत अधिक एसिड होता है। अगर पेट सुरक्षात्मक बाधा म्यूक्स न हो तो एसिड पेट को नुकसान पहुंचा सकता है परत को काट सकता है। जब इस म्यूक्स की लेयर कम हो जाती है या एसिड स्त्राव (सेक्रीसन) ज़्यादा होता है तो अमाशय की परत में जलन होने लगती है जिसे गैस्ट्रिटिस कहा जाता है। बैक्टीरिया, आईब्रुप्रोफेन, बहुत अधिक शराब, या तनाव जैसे दर्द रिलीवर के नियमित उपयोग द्वारा भी हो सकता है। आप कभी-कभी इसे ओवर द काउंटर एंटासिड या प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के साथ इलाज कर सकते हैं।

पेस्टिक अल्सर

उपरोक्त कारणों से पेट की परत या छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में घाव हो सकते हैं। इसका आम कारण बैक्टीरिया है लेकिन एस्पिरीन, आईबुप्रोफेन और अन्य दर्द निवारक दवाओं के दीर्घकालिक उपयोग से भी हो सकता है। धूम्रपान करते हैं या तम्बाकू खाते हैं, उन्हें ये अल्सर अधिक बार मिलता है।

वायरस या गैस्ट्रिक फ्लू

पेट फ्लू आंतों में एक वायरल संक्रमण है। इससे पतले पानीदार दस्त, ऐंठन या मतली हो सकती है, यह किसी संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने या उसके साथ तौलिये आदि सांझा करने या दूषित संक्रमित भोजन के माध्यम से हो सकता है। इसका कोई इलाज नहीं है, केवल लक्षणों का इलाज यथा बुख़ार की दवा निर्जलिकरण डी हाइड्रेशन हेतु जीवन रक्षक घोल ले सकते हैं। या बचाव हेतु हाथ धोना व वस्त्र साझा न करना संक्रमित भोजन से बचना जैसे उपाय कर सकते हैं।

खाद्य विषाक्ता

फूड पाइजनिंग

भोजन में बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी इस बीमारी का कारण बनते हैं। फूड पाइजनिंग से दस्त, मतली और उल्टी हो सकती है। यह संक्रमित भोजन खाने से होता है। यह आमतौर पर अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन यदि आप निर्जलित यानि डी हाइड्रेशन से ग्रसित हैं और जीवन रक्षक घोल से ठीक नहीं हो रहे तो तुरंत चिकित्सीय मदद लें चिकित्सक आइ वी फ्लूइड व एंटी बायोटिक दे सकते हैं। अगर किसी को फूड पॉइजनिंग के कोई लक्षण हैं और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हैं या फिर कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली कोम्प्रोमिज्ड इम्युनिअी यथा एच आइ वी या अन्य रोग है तो उसे तुरंत चिकित्सीय सहायता लेनी चाहिए।

अपेंडीसाइटिस - परिशिष्ट

(अपेंडीक्स) एक उंगली के आकार का अंग है जो पेट के निचले दाहिने हिस्से में की शुरूआत में पाया जाता है। यह जानवरों तथा ऊंटों में तो भोजन संग्रह का काम करता है लेकिन मानव में धीरे धीरे सिकुड़ गया है क्योंकि सदियों से मानव शरीर को भोजन भंडारण की ज़रूरत नहीं रही। यह स्पष्ट नहीं है कि यह मानव शरीर में अब क्या करता है, लेकिन जब यह संक्रमित होकर सूजन कर देता है तो फट भी सकता है तब इसे निकालने हेतु ऑपरेशन करना पड़ता है क्योंकि इसके फटने से बैक्टीरिया सारे पेट में फैल सकते हैं। पहले पेरिटोनाइटिस फिर मृत्यु तक हो सकती है। शुरुआत में एंटी बायोटिक व आइ वी फ्लूइड से ठीक हो सकता है लेकिन बार बार होने की शंका होती है।

गाल स्टोनज

आमतौर पर पित्ताशय की पथरी - उन टयूबों या नलिकाओं को ब्लॉक कर देती हैं जिनके द्वारा बाइल नामक द्रव्य जिगर व अग्न्याशय द्रव्य, पित्ताशय की थैली से छोटी आंत तक पहुंचता है के बीच चलते हैं। आम लक्षण पेट दर्द हैं- मतली, उल्टी बुखार, गहरे रंग का मूत्र और हल्के मटमैले रंग का मल भी हो सकते हैं। पत्थर अक्सर अपने आप निकल सकते हैं लेकिन अगर वे नहीं निकलते तो सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है।

हर्निया

(इन कार्सटरेटिसडहर्निया)

हर्निया तब होता है जब आंतों का एक हिस्सा के पेट की दीवार के माध्यम से स्लाइड करता है। जब यह मुड़ जाता है यानि मरोड़ खा लेता है तो मरोड़ के बाद के हिस्से की रक्त की आपूर्ति से कट जाती है, जिस तरह हर्ट अटैक में हर्ट, यह आपके पेट में गंभीर दर्द पैदा कर सकता है। समस्या को ठीक करने के लिए अक्सर सर्जरी की जल्दी ज़रूरत होती है।

क़ब्ज़: सप्ताह में तीन से कम मल त्याग होने पर कब्ज़ होना माना जाता है। व्यायाम, ख़ूब पानी और ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें बहुत सारे फाइबर खाना जो कब्ज़ नहीं होने देते इसमें बचाव कर सकते हैं होते हैं, साबुत अनाज सलाद आदि, मदद कर सकते हैं, कब्ज़ भी पेट दर्द कारणों में से एक हो सकता है।

अग्न्याशय शोथ

(पेंक्रीएटाइटिस)

ऐसा तब होता है जब अग्न्याशय

बाक़ी पेज 11 पर

शेष.... प्रथम पृष्ठ

विदेशी सरकारों ने भी जोर दिया है क्योंकि उन्हें यहां बड़ा बाज़ार नज़र आता है। हम भी ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों के प्रमाण पत्रों से गदगद हो जाते हैं, पर कोरोना के दौरान देश ने जो पीड़ा भुगती है, वह हमारी हक़ीक़त बयान कर गई है।

समाजवाद आउटडेटेड हो गया, पर अनियंत्रित पूंजीवाद भी भारत की गरीब जनता पर लादना अन्याय है। हमने फ्री मार्केट को झप्फा डाल दिया है। यही कारण है कि हमारी नीतियाँ रईस बढ़ा रही है। यह नीति पश्चिम में सफल रही हैं, पर हमारी परिस्थिति बिल्कुल अलग है। किसानों ने तीन क़ानूनों का विरोध अकारण नहीं किया। वह जानते हैं कि वह कॉरपोरेट का मुक़ाबला नहीं कर सकते। हर नीति परिवर्तन को इस तरह पेश किया जाता है कि जैसे बहुत जनकल्याण होगा। सभी सरकारें विकास पर ज़ोर देती रही हैं, पर कोई यह नहीं देखता कि विकास का फल बराबर बंटता है या नहीं? वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक आनिन्दयो चक्रवर्ती के अनुसार 'जिस वक़्त वह रिकॉर्ड मुनाफ कमा रहे थे भारत का कॉरपोरेट वर्ग कम टैक्स देकर बचा रहा। पिछले दस वर्ष में कुल टैक्स आमदन में कॉरपोरेट का योगदान 36 प्रतिशत से गिरकर 23 प्रतिशत रह गया है।' यह वह समय था जब भारी संख्या में भारतीयों की आमदन में भारी गिरावट हुई थी, पर 1 प्रतिशत सुपर रिच की बल्ले-बल्ले थी। वह हमारी सार्वजनिक नीति की भारी असफलता है कि ग़रीब खुद तरक्क़ी करने की जगह ख़ैरात पर निर्भर है। पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन ने लिखा है, ''लोकतांत्रिक सरकार वैश्वीकरण के फल को बराबर बांटने की अपनी ज़िम्मेवारी से पीछे हट गई है। हमारे यहां ग़ैर बराबरी का जो स्तर है वह लोकतंत्र के अनुरूप नहीं। बात बिल्कुल सही है। असमानता नैतिक तौर पर ग़लत है, राजनीतिक तौर पर नाशक है और लोकतंत्र के लिए ख़तरा हैं जहां अभी भी इतनी दरिद्रता है, भूख है, लाचारी है, बीमारी है, कुपोषण है, बेरोज़गारी है वहां अगर अरबपतियों की संख्या दुनिया में तीसरे नंबर पर है तो ज़रूर कुछ गड़बड़ है। हमारी जायज़ उपलब्धियां हैं, पर अब जबकि हम एक और गणतंत्र दिवस मना कर हटे हैं, हमें अपनी दिशा और रफ्तार पर फिर से नज़र दौड़ाने की बहुत ज़रूरत है। नई दिल्ली के इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति हटा कर इसे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में मिलाने को लेकर दुर्भाग्यपूर्ण विवाद खड़ा हुआ है। इंडिया गेट और अमन जवान ज्योति से हम में से बहुत भावनात्मक लगाव रहा है इसलिए एकदम तकलीफ हुई है, पर सरकार ने जो किया वह ग़लत नहीं है। एक, ज्योति को मिटाया नहीं गया राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति में शामिल किया गया है। दूसरा, अंग्रेजों द्वारा 1921 में बनाए गए इंडिया गेट के नीचे यह ज्योति अस्थाई अवस्था थी। 1 सितंबर 1972 को रक्षामंत्री जगजीवन राम ने एक प्रश्न के उत्तर में संसद में बताया था कि, ''अमर ज्योति के साथ अस्थाई युद्ध स्मारक बन चुका हैं स्थाई युद्ध स्मारक बनाना विचाराधीन है।'' दुख की बात है कि न वह सरकार और न ही बाद की सरकारें ही राजधानी में भव्य युद्ध स्मारक बना सकी।

सही बात यह है कि हमारे प्रशासक सत्ता के ऐसे लालची बन चुके हैं कि वह हर वह अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल करने में ही अपनी शान समझते हैं कि देश की जनता को पेट की भूक मिटाने के ग़म से ही मुक्ति न पायी। यही वजह है कि हमारे प्रधानमंत्री और सरकार के दूसरे ज़िम्मेदारों को कभी यह ग़ैरत नहीं आई कि वह तो हज़ारों करोड़ रुपए की मालियत के हवाई जहाज़ों में सफर करें, लाखों रुपए के कीमती कपड़े इस्तेमाल करें, शान ओ शौकत की ज़िन्दगी बसर करे और देश के 90 फीसद लोग दो समय की रोटी के लिए तरसते रह जाएं जबकि लोकतंत्र का तक़ाज़ा यह है कि राजा और प्रजा दोनों की ज़िन्दगी के स्तर में समानता होनी चाहिए। मोदी जी ने नए भारत का शिगूफा छोड़कर मुद्दे को अधिक उलझा दिया है और इस अनोखी बात से आजिज़ आकर ही अब देश की जनता अपने प्रधानमंत्री जी से यह मांग करने लगी है कि हमारे पुराने दिन लौटा दीजिए ''असल में उनके सामने सातवीं दशक का एक वह प्रधानमंत्रल लाल बहादुर शास्त्री भी है जो अपना फटा हुआ कुर्ता सीकर ठंड के मौसम में कोट के नीचे पहनने के लिए रख लेते थे।

एक केंद्रीय मंत्री के तौर पर जब शास्त्री जी को मास्को जाना पड़ा तो जवाहर लाल नेहरू का ओवरकोट मांगकर ले गए, केन्द्रीय मंत्री रफी अहमद किदवई के निधन पर उनकी आख़िरी रसूमात अंजाम देने वालो ने देखा कि खादी के कुर्ते के नीचे वह एक फटी बनियान छुपाए हुए थे, आज देश के मामूली से मामूली लीडर जो वस्त्र पहनता है वह खादी का होते हुए भी हज़ारों लाखों का होता है। पांच सितारा होटलो, होटलों के एयरकंडीशन कमरों में रहता है, सफर के लिए प्रथम श्रेणी या चार्टर्ड हवाई जहाज में सवार होता है। मंत्री और ऊंचे दर्जे के दूसरे नेता हेलिकॉप्टर का प्रयोग भी टैक्सी की तरह करते हैं, किसी राज्य में बाढ़ आती है तो हमारे मंत्री महाराज वहां का हवाई दौरा करके लौट आते हैं, उन्हें जमीन पर क़दम रखकर स्थिति जानने और प्रभावितों के बहते आंसू पोंछने की चिंता नहीं होती, इसके विपरीत जंगे आज़ादी के दौरान हमारे राष्ट्रीय नेताओं की स्थिति का सर्वेक्षण करने किसी जगह जाते तो आम सी सवारी का प्रयोग करते थे ताकि वहां की असल स्थिति का अंदाज़ा कर सकें, महात्मा गांधी बंगाल के नवा खाली में साम्प्रदायिक दंगे की ख़बर सुनकर कच्चे रास्ते को पैदल और बैलगाड़ी से पार करके पहुंचे थे लेकिन आज़ादी के बाद इस देश के रात-दिन ही बदल गए। अब मंत्री महोदय ऐसे कार्यों के लिए हवाई जहाज या हेलिकॉप्टर का प्रयोग करते हैं। पांच सितारा होटल, या रेस्ट हाउस में आराम करते हैं, चमचमाती लग्जरी कारें उनके लिए उपलब्ध कराई जाती है हालांकि ज़मीनी हकायक का अंदाज़ा लगाने के लिए ज़रूरी है कि साहब लोग आराम के उन स्रोतों से बाहर निकले, विशेषकर जनता के सेवक इस तथ्य को ज़ेहन में बैठा लें कि वह ग़रीबों के नेता हैं जिन्हें दो वक़्त पेट भर खाना नहीं मिलता, जिन के सर पर छत नहीं है, जो रोज़गार से वंचित है जब तक ऐसे फाक़ापरस्तों के लिए वह काम नहीं करेंगे, उस समय तक अमीरी और ग़रीबी का फर्क दूर नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा जैसा कि आज तक होता रहा है।□□

शेष.... मोदी सरकार के लिए....

कॉलेज बनाया जाता है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन किया जाता है। 2017 में दोनों सदनों के 776 सांसदों और 4,120 विधायकों से इलेक्ट्रोलर कॉलेज बनाया गया था। मोदी ने इसके बारे में हाल ही में आरएसएस के नेताओं, भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह के साथ विस्तृत चर्चा की। ऐसे कयास हैं कि आरएसएस ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए अपनी पसंद के उम्मीदवारों के कुछ नाम भी सुझाए हैं। कहा जाता है कि मोदी इस बार में देश के शीर्ष सांविधानिक पद पर किसी दक्षिण राज्य, संभवत: तमिलनाडू से किसी महिला को देखना चाहते हैं। संभावित उम्मीदवारों में दो राज्यपालों के नाम है।

एक बात बहुत स्पष्ट दिख रही है कि न तो कोविंद को दूसरा कार्यकाल मिलने जा रहा है और न तमिलनाडू को पदोन्नत करने पर विचार हो रहा है। संभवत: इस बारे में जुलाई के पहले सप्ताह में ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा और मोदी की शैली के अनुरूप कोई चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है।□□

शेष.... पेट दर्द...

(पेंक्रीआज) जो शरीर को चीनी की प्रक्रिया में मदद करता है और भोजन को पचाता है, सूजन हो जाता हैं ऊपरी पेट में दर्द हो सकता है जो खाना खाने के बाद बढ़ जाता हैं बुख़ार मतली व उलटी हो सकती है, गंभीर स्थिति में आइफ्लूइड व एंटी बायोटिक से उपचार कियाजाता है।□□

शेष.... मंज़र पस-मंज़र

है और इसकी बहुत सी वर्तमान विकृतियों को भी कम किया जा सकता है। अगर हम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को देखें, तो देश में 11 प्रतिशत अपराध महिलाओं के खिलाफ़ होते हैं, और जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उनमें पांच प्रतिशत महिलाएं होती हैं। सिर्फ इसी गणित को जोड़ लें, तो पुलिस में महिलाओं की संख्या 16 प्रतिशत होनी ही चाहिए। तमाम क़ानूनी प्रावधान कहते हैं कि महिलाओं की गिरफ्तारी या उनसे जुड़े मामले महिला पुलिसकर्मियों को ही सौंपे जाने चाहिए। महिलाओं के अलावा बच्चों से जुड़े मामले भी महिला पुलिसकर्मियों को सौंपने को ज़्यादा बेहतर माना जाता है। समाजशास्त्री कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी महिलाओं की भूमिका बढ़ाने की बात करते हैं। कहा जाता है कि अगर मामलों की जांच में महिला पुलिसकर्मियों की भूमिका बढ़ाई जाती है, तो इससे इस काम की कुशलता बढ़ सकती है।

महिलाओं को सुरक्षा बलों में शामिल करने का तर्क कोई नया नहीं है। पुलिस में उनकी भर्ती भी काफी लंबे समय से होती रही है। वर्ष 1933 में पहली बार त्रावणकोर रॉयल पुलिस में महिला पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। इसके छह वर्ष बाद कानपुर में महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती इसलिए की गई थी क्योंकि श्रमिक असंतोष के दौरान महिला आंदोलनकारियों से निपटना पुरुष पुलिस वालों के लिए मुश्किल हो रहा था। इसके बाद बॉम्बे, मुद्रास ओर बंगाल प्रेसिडेंसि में कुछ महिलाओं को पुलिस में भर्ती किया गया। आज़ादी के बाद यह काम पूरे देश में शुरू हुआ, लेकिन इसे कभी प्राथमिकता नहीं मिली। 2013 में केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सुझाव दिया था कि हर थाने में कम से कम तीन महिला सब-इंस्पेक्टर और दस महिला कांस्टेबल होने चाहिए। अभी तक यही लक्ष्य ठीक से हासिल नहीं हुआ, स्थायी समिति की सिफारिश वाला 33 प्रतिशत का लक्ष्य तो बहुत दूर की कौड़ी प्रतीत होता है।

बेकाबू ना हो महंगाई

रिज़र्व बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी (एमपीसी) ने ब्याज़ दरों में कोई बदलाव नहीं किया। यह लगातार दसवां मौक़ा है जब दरें जस की तस रखी गईं। आख़िरी बार 22 मई 2020 को पॉलिसी रेट में बदलाव हुआ था। तब ब्याज़ दरें घटाई गई थीं। आरबीआई जिस दर पर बैंकों को उधार देता है, उस रेपो रेट को 04 प्रतिशत पर बनाए रखा गया। आरबीआई के पास पैसा जमा करने पर बैंकों को मिलने वाली ब्याज़ दर यानि रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35 प्रतिशत पर रहने दिया गया। अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार आरबीआई रिवर्स रेपो रेट में 0.15-0.40 फीसदी तक बढ़ोत्तरी करेगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। रिजर्व बैंक के दरों में बदलाव न करने की वजह यह है कि वह इकॉनामिक रिकवरी को सपोर्ट देना चाहता हे। इससे पहले बजट में सरकार ने वित्त वर्ष 2023 में केपिटल एक्सपेंडिचर में 35 प्रतिशत से अधिक बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव रखा था। केन्द्र कोा ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अभी कंस्यूमर डिमांड कमजोर हैं इस वजह से निजी क्षेत्र की ओर से बहुत निवेश नहीं हो रहा। सरकार को लगता है कि उसके अधिक पैसा खर्च करने से आर्थिक विकास दर में तेज़ी आएगी। लिहाज़ा रोज़गार बढ़ेगा और लोग अधिक पैसा खर्च करेंगे। इससे डिमांड की दिक्क़त दूर हो सकती है। रिजर्व बैंक ने ब्याज़ दरों में बदलाव ना करके एक तरह से सरकार की इस नीति को समर्थन दिया है। इतना ही नहीं, रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि जब तक ग्रोथ टिकाऊ नहीं हो जाती, तब तक वह कर्ज महंगा नहीं करेगा। लेकिन इसमें एक पेच है। देश में महंगाई बढ़ रही है। खुदरा महंगाई दर भले ही रिजर्व बैंक के 06 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से कम हो, लेकिन थोक महंगाई दर बहुत ऊंची है। इससे खुदरा महंगाई दर आने वाले समयम में बढ़ेगी। इस बीच, कच्चे तेल के दाम में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। रिजर्व बैंक को यह पक्का करना होगा कि रुपया कमज़ोर न हो। यह भी देखना होगा कि सस्ती ब्याज़ दरों की वजह से किसी भी एसेट क्लास में बुलबुला ना बने और सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई बेकाबू ना हो क्योंकि वह खासतौर पर ग़रीबों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होती है।

शेष.... क्या चीन के चंग्ल में....

बुनियाद चरित्र हैं आलम यह है कि वहां कभी भी फौजी जनरल प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की कुर्सी पर काबिज़ हो जाता है। अगर तख़्तापलट सीधे तौर पर न हो सके, तो फौजी जनरल परदे के पीछे से शासन चलाते हैं, जैसे अभी इमरान को मुखौटा बनाकर वे कर रहे हैं। अलबत्ता, पाकिस्तान में जब-जब सैन्य शासक आए हैं, भारत के साथ उसके रिश्ते सुधरे ही हैं। हां, चीन का दख़ल और अगर बढ़ता है, तो एकमात्र खतरा वही हो सकता है, जिसका अंदेशा भारतीय थलसेना प्रमुख ने ज़ाहिर किया है। वह मानते हैं कि अगर तनाव बढ़ा, तो अब चीन और पाकिस्तान, दोनों मोर्चों पर हमें एक साथ लड़ना होगा। मगर फिलहाल इसके संकेत नहीं है।□□

SHANTI MISSION (HINDI WEEKLY) NEW DELHI Postal Registration No. DL(C)-01/1266/2021-23
Publishing Date : **20 fab.2022** Posting Days : **MON. - TUE**. at **N.D.P.S.O.** New Delhi-110002 R.N.I. 57270/93

•यूक्रेन का गहराता संकट•पुलिस में महिलाएँ•बेकाबू ना हो महंगाई

यूक्रेन का गहराता संकट

रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल कर कोरोना से उबर रही दुनिया को युद्ध में धकेल दिया है। रूसी सेना यूक्रेन पर बमबारी कर रही है। इससे पहले पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादियों के दो इलाकों दोनेत्स्क और लुहांस्क को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्वतंत्र देशों के रूप में मान्यता देने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने रूस के ख़िलाफ़ अपना रुख़ कड़ा ज़रूर कर लिया है, लेकिन यूक्रेन का संकट जल्द समाप्त होता नहीं दिख रहा है। दोनेत्स्क और लुहांस्क में रूस समर्थक अलगाववादियों का वर्चस्व है और उनका यूक्रेन के साथ टकराव चल रहा था, मगर 2014 में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम समझौता हो गया था और तब से वहां शान्ति क़ायम थी। मगर अब इन दो क्षेत्रों को स्वतंत्र देश की मान्यता देकर रूस वहां अपनी फौज घुसा कर यूक्रेन के लिए चुनौती पेश कर सकता है। ग़ौर करने वाली बात यह है कि ताज़ा संकट के लिए पुतिन ने अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी देशों के संगठन नाटो को ज़िम्मेदार ठहराया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अमेरिका यूक्रेन को नाटो में शामिल कर रूस की सुरक्षा के लिए चुनौती पैदा कर सकता है। स्थिति की गंभीरता का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि एक ओर जहां यूक्रेन की सीमा में रूसी सैनिकों और टैंकों का जमावड़ा बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका की अगुआई में नाटो यूक्रेन को समर्थन दे रहा है। पुतिन ने तो यहां तक कहा है कि आधुनिक यूक्रेन का तो स्वतंत्र अस्तित्व कभी रहा ही नहीं है, वह कम्युनिस्ट नेता व्लादिमीर लेनिन की अगुआई में हुई बोल्शेविक क्रांति की देन है। मौजूदा संकट अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसे अभी अभी अफग़ानिस्तान में घनघोर नाकामी के बाद अपने क़दम वापस खींचने पड़े हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस के ख़िलाफ़ प्रतिबंधों की घोषणा की है, जिसे कई देशों ने समर्थन दिया है, इससे रूस के लिए आर्थिक चुनौती पेश आ सकती है। मगर हालात से ऐसा लगता है कि रूस को अपने इशारे पर नचाने वाले पुतिन घड़ी की सुई को उल्टी दिशा में घुमाना चाहते हैं। जहां तक भारत की बात है, तो संयुक्त राष्ट्र में उसका रुख़ एकदम सही है कि वहां तनाव पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। भारत की चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि यूक्रेन में 20 हजार से अधिक भारतीय नागरिक और छात्र हैं। पिछले दिनों एक स्पेशल यान से यूक्रेन से कुछ छात्र तो लौट भी आए हैं। यूक्रेन और रूस की सीमा पर बढ़ते तनाव को जल्द खत्म नहीं किया गया तो यह शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद अब तक के सबसे बड़े टकराव में बदल सकता है, जिसकी भारी कीमत सबको चुकानी पड़ेगी।

पुलिस में महिलाएँ

यह ज़रूरत लंबे समय से महसूस होती रही है, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। यही वजह है कि पुलिस बलों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने का मामला लगातार टलता रहा। यह बहुत पहले से कहा जाता रहा है कि पुलिस में कम से कम एक तिहाई महिलाएं होनी चाहिए। उनकी संख्या बढ़ाने की कोशिशें भी हुईं, लेकिन बात एक हद से आगे नहीं पहुंची। कई जगह महिला थाने भी बनाए गए, जिनमें सारी ज़िम्मेदारियां महिलाओं के ही हाथ में दी गई। इन थानों ने अपना प्रभाव भी छोड़ा, लेकिन ऐसे थानों की सीमित संख्या के कारण बात एक हद से आगे नहीं बढ़ी। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम में कहा था कि पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। अब पुलिस के आधुनिकीकरण और सुधार के लिए बनी संसद की स्थायी समिति ने पुलिस बल में महिलाओं की संख्या 33 प्रतिशत करने के लिए रोडमैप बनाने की सिफारिश की हैं सुझाव यह है कि सिर्फ पुरुषों के ख़ाली पदों को महिलाओं से भरने का काम ही नहीं किया जाए, बल्कि महिलाओं के लिए अलग से नए पद भी सृजित किए जाएं। अभी पुलिस बलों में महिलाओं की तदाद 10 प्रतिशत से कुछ ही अधिक है। समाजशास्त्री मानते हैं कि पुलिस में महिलाओं की संख्या बढ़ाकर इसके चेहरे को मानवीय बनाया जा सकता

बाक़ी पेज 11 पर

पड़ोसी कजाखस्तान संकट में अपनी विफलता से चिंतित चीन

नए वर्ष 2022 की शुरुआत में ही चीन के पड़ोसी देश कजाखस्तान में जन विद्रोह हो गया। यह विद्रोह वहां वाहनों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाली सी.एन.जी. के दामों में बढ़ोत्तरी को लेकर हुआ था, जिसके चलते लोग सड़कों पर आकर सरकार विरोधी प्रदर्शन करने लगे। कजाखस्तान के सबसे बड़े शहर अल्माती और दक्षिण पश्चिम राज्य मैंगिस्टाऊ में सबसे अधिक विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके चलते प्रधानमंत्री अस्कार मामिन ने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव द्वारा कजाखस्तान में 15 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा करने के बाद हालात और बिगड़ने लगे, जिसे देखते हुए टोकायेव ने अपनी सेना को विद्रोहियों को बिना चेतावनी के गोली मारने के आदेश दे दिए।

रूस और चीन के बीच कजाखस्तान को लेकर जो खींचतान पिछले दिनों चली, उससे यह बात साफ हो जाती है कि जिस चीन का ज़मीन को लेकर विवाद लगभग अपने सारे पड़ोसियों के साथ चल रहा है, उसे अपने निकटतम पड़ोसी कजाखस्तान के अंदरखाने होने वाले घटनाक्रम के बारे में कानो-कान ख़बर तक न लगी और और रूस की सेना विद्रोह दबाने वहां पहुंच गई।

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूसी सेना के कजाखस्तान पहुंचने के एक दिन बाद फोन पर टोकायेव से बात कर अपना समर्थन उनके लिए जताया, साथ ही विद्रोहियों को रोकने के लिए टोकायेव द्वारा उठाए गए दमनकारी क़दमों का समर्थन भी किया। चीन के टोकायेव का समर्थन करने का सीधा मतलब यह है कि चीन वहां सत्तादल के साथ है, न कि कजाखस्तान की जनता के साथ।

इस घटना के बाद चीन पर प्रश्न उठने लगे कि वह जिस देश के साथ 1782 किलोमीटर से ज़्यादा की सीमा सांझी करता है, उसमें जनविद्रोह और उसे दबाने के लिए रूसी सेना के आगमन की भनक उसे कैसे नहीं लगी। जानकारों की राय में चीन के खुफिया तंत्र की विफलता के पीछे पहला कारण है कोरोना महामारी, जिसकी शुरुआत से ही ही राजधानी नूरसुल्तान (पुराना नाम आस्ताना) में चीनी राजनयिकों ने खुद को डिप्लोमैटिक कम्पाउंड में सुरक्षित कर लिया था, जिसके चलते वे हर तरह के बाहरी संपर्क से कट गए थे। दूसरा कारण चीन को अंतर्राष्ट्रीय मामलों की वह समझ नहीं है जो पश्चिमी दुनिया को है और चीनी शीर्ष कमांड वे ख़बरें सुनता है जो वह सुनना चाहता है, जिसके चलते खुफिया जानकारी देने वाले तथाकथित पंडितों ने वैसी ही ख़बरें चीन के राजनयिकों को मुहैया करवाई जिनसे पेइचिंग खुश होता है।

तीसरा कारण वहां चीनी मामलों के जानकार 62 साल के कोन्सतानतीन साइरोएजकिन का कजाखस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा दल द्वारा गिरफ्तार किया जाना और उन पर चीन को देश की खुफिया जानकारी मुहैया करवाए जाने को लेकर उन्हें 10 वर्ष के कारावास की सज़ा देना। चौथा कारण है कजाखस्तान का हाल के सालों में अमेरिका और तुर्की की ओर झुकाव। हालांकि दोनों देश इस समय एक दूसरे के विरोधी हैं, कजाखस्तान मुस्लिम राष्ट्र है और चीन चीन शिनजियांग उईगर स्वायत्त प्रांत में उईगर मुसलमानों पर बेतहाशा अत्याचार कर रहा है, जिसके चलते कजाख जनता बड़ी संख्या में चीन के विरुद्ध है।

वहीं रूस की बात करें तो वर्ष 1991 में उससे आज़ाद होने के बाद भी कजाखस्तान पर रूस के राजनीतिक, सैन्य, राजनयिक और संभ्रात व्यापारी वर्ग की पकड़ मज़बूत है। वहीं ड्रैगन के व्यापारिक हितों को नुकसान न पहुंचे, इसलिए उसने कजाखस्तान के सत्ताधारी दल का साथ देना ज़्यादा मुनासिब समझा।

दूसरी ओर टोकायेव द्वारा रूस से मदद मांगना उनकी राष्ट्रीय स्तर पर मज़बूत पकड़ को दिखाता है। देश की रक्षा के लिए टोकायेव की रूस पर निर्भरता चीन के लिए चिंता का कारण तो है ही, साथ ही यह पूरी घटना देश के पूर्व राष्ट्रपति नूरसुल्तान नज़रबायेव की पकड़ को कजाखस्तान पर से ख़त्म होने की कहानी भी कहती है।

चीन के कजाखस्तान के साथ 30 वर्ष पुराने राजनयिक संबंध है, बावजूद इसके जिस तरह से पिछले दिनों घटनाक्रम ने दिखा दिया कि दुनिया को जीतने का सपना देखने के बाद भी चीन के परिपक्व थिंकटैंक की नाकामी के चलते उसे निकटतम पड़ोसी कजाखस्तान के बारे में जानकारी तक नहीं थी और वह तुर्की और अमेरिका जैसे देशों के करीब चला गया। ऐसे हालात में चीन को नए सिरे से मध्य एशियाई सहयोगी देशों में अपनी ज़मीन तलाशनी होगी।□□

ज़रूरी ऐलान

आपकी ख़रीदारी अवधि पते की चिट पर अंकित है। अवधि की समाप्ति से पूर्व रक़म भेजने की कृपा करें।

रक़म भेजने के तरीक़े:-

❶ मनीआर्डर द्वारा ❷ **Paytm** या **PhonePe** द्वारा **9811198820** पर
SHANTI MISSION
❸ ऑनलाइन हेतु बैंक खाते का विवरण
SBI A/c **10310541455**
Branch: **Indraprastha Estate**
IFS Code: **SBIN0001187**

अपने प्रिय अख़बार साप्ताहिक शांति मिशन को इंटरनेट पर देखने के लिये लॉगऑन करें:
www.aljamiat.in ——— www.jahazimedia.com
Mob. 9811198820 — E-mail: Shantimissionweekly@gmail.com

ख़रीदारी चन्दा

वार्षिक	Rs.130/-
6 महीने के लिए	Rs.70/-
एक प्रति	Rs.3/-

जानकारी के लिये सम्पर्क करें
साप्ताहिक
शांति मिशन
1, बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग,
नई दिल्ली-110002
फोन : 011-23311455

जमीअत ट्रस्ट सोसायटी की तरफ से मुद्रक, प्रकाशक मोहम्मद तैयब ख़ान ने शेरवानी आर्ट प्रिंटर्स, 1480, क़ासिमजान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से छपवाकर मदनी हाल, न. 1, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित किया। संपादक:- मोहम्मद सालिम, फोन:- 23311455, 23317729, फैक्स:- 23316173